RNI No. MPHIN/2018/76422

प्रेरणा स्त्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

माही की गूंज

बेबाकी के साथ..सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

अपनी खुशी को भविष्य की किसी सही तारीख के लिए स्थगित मत करो। अभी खुश रहें। कल अपने आप ही बन जाएगा। श्रीश्री रविशंकर

वर्ष-02, अंक - 38 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 25 जून 2020 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

एलएसी पर शांति के लिए भारत और चीन में हुई बात, बनी यह सहमति

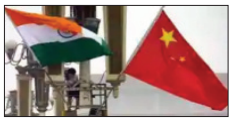

नईदिल्ली एजेंसी। भारत और चीन के बीच बुधवार को एक बार फिर राजनयिक स्तर की बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले इलाकों से सैनिकों को हटाने को लेकर पहले बनी सहमति पर अमल से सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में स्थिति सहित सीमावर्ती क्षेत्रों के घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय पक्ष ने पूर्वी लद्दाख में हुए हालिया घटनाक्रम पर अपनी चिंता से उन्हें अवगत कराया।

चीन के साथ राजनयिक बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष ने 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प का मुद्दा उठाया, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इस पर जोर दिया गया कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरा-पूरा सम्मान करें। मौजूदा हालात के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर संवाद बनाए रखने की सहमति बनी।

लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तनाव कम करने के तौर-तरीकों को लेकर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये भारत-चीन के बीच कूटनीतिक बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पूर्वी एशिया) नवीन श्रीवास्तव और चीनी विदेश मंत्रालय में महानिदेशक वू जियांगहो के बीच बातचीत हुई।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें पीएम मोदी के लिए 'आपदा में अवसर': दिग्विजयसिंह

भोपाल एजेंसी। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफजमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और अन्य कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर उतरकर बढ़ी कीमतों के खिलाफअपना विरोध दर्ज करवाया।

दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में अन्य कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने को लेकर अपना विरोध जताते हुए रोशनपुरा चौराहे से मुख्यमंत्री आवास तक साइकिल पर मार्च निकाला।

दिग्विजय ने कहा कि श्आज जब जनता कोरोना के संकट में त्रस्त है, महंगाई बढ़ती जा रही है लोग भूखे मर रहे हैं और केंद्र सरकार ने लगातार 18वें दिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं- आपदा में अवसर, उनके लिए कोरोना आपदा में अवसर है पैसा कमाने के लिए।'

कालीघाटी और बाछीखेड़ा में मनरेगा तालाब में चली जेसीबी

भ्रष्ट उपयंत्री अहिरवार का मायाजाल, रात के अंधेरे में मजदूरों के हक पर डाला डाका

कालीघाटी में नाला, तो बाछीखेड़ा में कुंए पर मशीन चलना बताकर भ्रष्टों को बचाकर दबाया जा रहा है मामला

ग्राम पंचायत कालीघाटी में इस तरह मनरेगा के कार्यों में हो रहा मशीनों का उपयोग।

ग्राम पंचायत बाछीखेड़ा में रात के अंधेरे में करवाया गया मशीनों से तालाब का कार्य।

इस तरह निमार्णाधीन तालाब पर दिखाई दे रहे है जेसीबी मशीन के निशान।

माही की गूंज, पेटलावद। गत दिनों ग्राम पंचायत कालीघाटी और बाछीखेड़ा में मजदूरों को हक पर डाका मरते हुए मनरेगा के तालाब में भारी मशीनों से काम किया गया। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों की, लेकिन जवाबदार जांच के नाम पर शासन को गुमराह कर अपने आपको और भ्रष्ट उपयंत्री, सचिव, सहायक सचिव और सरपंच को बचाते नजर आए। मगर फर्जी जांच से गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर बने गलत पंचनामें को फाड़ कर बता दिया कि अब भ्रष्ट इस तरह से खुलेआम की गई चोरी को अपनी फर्जी जांच के नाम पर दबा नहीं सकते।

मामला नं.01 फर्जी बिल लगाकर बिना रोड बनाए पैसा एठने वाली पंचायत ने अब मनरेगा के तालाब में चलाई जेसीबी

विकास खण्ड पेटलावद की ग्राम पंचायत में फैले भ्रष्टाचार के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। मजदूरों को रोजगार देने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत कालीघाटी में बन रहे मनरेगा के तालाब में जेसीबी से काम होने का मामला सामने आया है। कालीघाटी के ग्रामीणों ने मामले की शिकायत सीईओ और तहसीलदार पेटलावद को जेसीबी से काम करते वीडियो सहित की है। ग्राम पंचायत कालीघाटी के सुखराम परमार, दिनेश मुनिया, रतन भूरिया, मड़िया मचार सहित पंचायत के ग्रामीणों ने लिखित आवेदन देकर ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव पर गंभीर आरोप लगाया हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि पंचायत के कस्याखाली ग्राम में रामा सोलंकी की बइड़ा वाली नाकी पर तालाब निर्माण किया जा रहा है। जिसका काम 08 दिन पहले ही शुरू हुआ था और शुरू में मजदूरों को लगाया गया, लेकिन मंगलवार-बुधवार को दिन-दहाड़े जेसीबी से तालाब की खुदाई कर दी। लोगों के वीडियो बनाने और रोकने के बाद भी जेसीबी से कार्य चलता रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि भ्रष्ट सरपंच-सचिव और सहायक सचिव द्वारा मजदूरों के हक का का काम छीन कर नियम विरुद्ध काम किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर पंचायत की ओर खड़ा रामा सोलंकी से जब जेसीबी नहीं चलवाने का कहा तो उसका कहना था कि मजदूर नहीं मिल रहे है, इसलिए काम जेसीबी से करना पड़ रहा है। मामले में जांच करने पहुंचे पटवारी सुमित सौलंकी का कहना है कि यहां गांव के ही एक व्यक्ति का कुंआ हैं जिसके लिए नाली खोदी जाने की बात कही जा रही हैं। मनरेगा के तालाब में जेसीबी भी चली हैं यहभी तय है, लेकिन मामले की पूरी पुष्टि अधिकारी ही करेंगे। मामले में अधिकारी शिकायत के बाद मौके पर नहीं पहुंचे हैं। पूरे मामले में जवाबदार गोलमाल कर मामले को निपटाने में लगे हैं। पटवारी के स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि किस तरह से मामले को घुमाकर ग्राम पंचायत को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का साफ कहना है कि मनरेगा के काम में भारी मशिनों का उपयोग किया जा रहा हैं और मजदूरों के हक पर डाका मारा जा रहा है। मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने से ग्रामीणजनों में निराशा है।

मामला नं.02 ग्रामीणों ने फाड़ा पंचनामा, चौकी पहुंचा मामला

ग्राम पंचायत बाछीखेड़ा के ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर गलत बनाया गया पंचनामा फाड़ा।

लॉकडाउन में रोजगार नहीं मिलने की शिकायत के बाद ग्राम पंचायत बाछीखेड़ा के लोगों को रोजगार देने के लिए ताबड़तोड़ दो तालाब स्वीकृत किए गए ताकि ग्राम के अब तक मजदूरी से वंचित लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन भ्रष्ट ग्राम पंचायत बांछिखेड़ा और महा भ्रष्ट उपयंत्री अहिरवार ने गरीब मजदूरों का निवाला एक बार फिर छीन लिया। अभी तीन दिन पहले उपयंत्री अहिरवार के प्रभार वाली ग्राम पंचायत कालीघाटी में पंचायत के मनरेगा तालाब जेसीबी चलने का वीडियो आया था। जिसकी जांच भी नहीं हुई थी कि एक और पंचायत में मनरेगा तालाब में मजदूरों के हक को जेसीबी कुचल दिया गया।

शेष पृष्ठ 3 पर पढ़े....।

आठ लाइन सड़क में हुई भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर जनजाति मंच सतत कर रहा प्रयास व धरना आंदोलन

सुनवाई नहीं होने पर जनजाति मंच के पदाधिकारी सीएम से मिलने जाएंगे भोपाल

मुआवजे को लेकर धरना प्रर्दशन करते पीड़ित व जनजाति मंच के पदाधिकारी।

आठ लाइन सड़क में आ रहे मकानों का मुआवजा नहीं मिलने पर जान चली जाए तो भी मकान खाली नहीं करने की कह रहे बात पीडित।

माही की गूंज, भामल। नारायण पालरा

दिल्ली से मुंबई तक बनने वाले आठ लाइन सड़क में झाबुआ जिले की सीमा में रहने वाले ऐसे कई रहवासी है जो वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं। परंतु उन्हें उनकी ही भूमि, मकान तथा खेती पर अधिकार नहीं है।

शासन ने भी वर्षों से रह रहे परिवारों के कब्जे वाली शासकीय भूमि के पट्टे भी देने की योजना बनाई और राजनीतिक दलों ने चुनावी लाभ भी लिया। परंतु उक्त आठ लाइन सड़क में अब भी ऐसे आदिवासी समाज के परिवार है जो, कई वर्षों से अपने गांव में रहकर व खेतीकर अपना पेट पाल रहे थे। जिस स्थान पर यह लोग रह रहे है वह जमीन ही सरकारी खाते की बताकर आठ लाइन सड़क में अधिग्रहण कर उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाकर बेघर किया जा रहा है। तो वहीं कई ऐसे भी किसान है, जिनकी भूमि आठ लाइन सड़क निर्माण में आ रही है, जिनका मुआवजा नाममात्र का ही दिया जा रहा है। मुआवजा तथा अपने अधिकारों की मांग को लेकर जनजाति मंच के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर तथा जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर हार चुके हैं। अब तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और न हीं जमीन दी जा रही है।

इसी तारत्मय में क्षेत्र के ग्राम वडलीपाड़ा में भी शुक्रवार को जनजाति संगठन तथा पीड़ित परिवारों द्वारा धरना देकर सरकार से मुआवजा देने तथा जमीन देकर आवास बनवाने की मांग की है। जनजाति मंच के रामचंद कटारा ने बताया कि थांदला में 18 दिन तक हमने धरना दिया था और अधिकारियों ने आस्वस्त किया था कि जांचकर उचित कार्यवाही कर मुआवजा तथा आठ लाईन सड़क में जमीन जाने से जो जमीन विहीन हो गए है उन्हें जमीन देकर आवास बनवाया जाएगा। काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक न तो कोई मुआवजा दिया गया और न ही जमीन।

रामचंद के साथ ही धरना स्थल पर मौजूद पीड़ितों ने अलग-अलग समस्या बताई। जिसमें तलावड़ा निवासी एक वृद्ध महिला जिनका पति-पुत्र दोनों काल के ग्रास में समा गए और बहु एवं छोटे-छोटे पोतो की परवरिश करना मुश्किल हो गया है। आठ लाईन सड़क निर्माण में वृद्ध महिला की जमीन व मकान जा रहे हैं। जिनका मुआवजा तक नहीं मिला है। ठेकेदार मकान खाली करवाने हेतु नए-नए हथकंडे अपना रहा है। जिसमें मकान के दरवाजे के आगे भारी भरकम पत्थर, ट्रैक्टर ट्राली में लाकर डाल दिए थे। तो वहीं एक किसान का कहना है कि मेरी करीब 12 बीघा जमीन आठ लाइन रोड में गई है। परंतु मुझे 4 बीघा का मुआवजा वह भी जमीन के मूल्य से काफी कम दिया गया है। ऐसे ही कई पीड़ितों ने अपनी-अपनी समस्या बताई।

जनजाति मंच के रामचंद कटारा ने गूंज को बताया कि जिले के सभी जनप्रतिनिधि व प्रशासन को ज्ञापन देकर धरना दे चुके हैं। समाधान हेतु एक बार भोपाल मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। अगर फिर भी समाधान नहीं हुआ तो हम हमारी मांगों को लेकर अनवरत धरना प्रदर्शन करेंगे। कटारा ने बताया कि करीब सवा सौ से अधिक ऐसे परिवार हैं जो वर्षों से यहां रह रहे है। परंतु उनकी जमीन को सरकारी बताकर मुआवजा नहीं दिया गया है। वहीं तलवाड़ा के 8-10 परिवार ऐसे हैं जिनकी 8 वे लाइन में जमीन जाने के बाद 1 इंच भी जमीन नहीं बची है। ऐसे परिवार आखिर अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? सरकार जल्द ही समाधान नहीं करती है तो पीड़ित परेशान होकर आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाएंगे।

पतंजलि के कोरोना की दवा बनाने का मामल पहुंचा कोर्ट

बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ केस दायर

मुजफ्फरपुर एजेंसी। योगगुरु बाबा रामदेव के कोरोना वायरस की दवा बनाने के दावे का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में बुधवार को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ देश को दवा के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए एक केस दायर किया गया है।

मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में समाजसेवी और भिखनपुरा निवासी तमन्ना हाशमी ने एक परिवाद पत्र दायर कर पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव तथा पतंजलि संस्था के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण पर आरोप लगाया है कि इन दोनों ने कोरोना वायरस दवा बनाने का दावा कर देश को धोखा दिया है। परिवाद पत्र में कहा गया है कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दवा श्कोरोनिल टैबलेटश् का ईजाद करने का दावा किया है, आयुष मंत्रालय ने इस पर प्रश्न उठाते हुए इस दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। परिवादपत्र में बाबा रामेदव और बालकृष्ण को आईपीसी की धारा 420, 120बी, 270, 504/34 के तहत आरोपी बनाया गया है। तमन्ना हाशमी ने बताया कि अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर की है।

रामदेव ने देश को नई दवा दी, पर जांच के बाद ही मिलेगी इजाजत-आयुष मंत्री

नईदिल्ली एजेंसी। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि के कोरोना वायरस के लिए कोरोनिल दवा बनाए जाने पर आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने बुधवार को प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि दवा के इस्तेमाल के लिए तभी हरी झंडी दी जाएगी, जब कंपनी द्वारा भेजी गई तमाम रिपोर्ट्स को सरकार अच्छे से जांच कर लेगी। आयुष मंत्रालय ने मंगलवार को कोरोनिल के लॉन्च किए जाने के बाद उसके प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी थी। मंत्रालय ने पतंजलि से कोरोनिल को लेकर जानकारी भी मांगी थी।

कोरोना वायरस का इलाज करने का दावा करने वाली कोरोनिल दवा को लेकर आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा, 'यह अच्छी बात है कि बाबा रामदेव ने देश को नई दवा दी है, लेकिन नियम के हिसाब से पहले आयुष मंत्रालय में जांच के लिए भेजी जानी चाहिए थी।' नाइक ने कहा, 'उन्होंने (पतंजलि) कहा है कि उन्होंने कोरोनिल को लेकर रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। हम उसे देखेंगे और जांच के बाद ही दवा के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी।'

वहीं, कोरोनिल के प्रचार पर रोक लगाए जाने के बाद पतंजलि ने कहा है कि यह एक कम्युनिकेशन गैप था, जोकि दूर हो गया है। सभी रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी गई हैं। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर बताया कि जो भी हमसे जानकारी मांगी गई थी, वह हमने आयुष मंत्रालय को दे दी है। बालकृष्ण ने ट्वीट किया, 'यह सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन व गौरव देने वाली है। जो कम्युनिकेशन गैप था, वह दूर हो गया है। क्लीनिकल ट्रायल के जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, उन सभी को 100 फीसदी पूरा किया है। इसकी सारी जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को दे दी है।'

साहित्यम डॉ रामशंकर चंचल की साहित्य साधना का अनुपम दस्तावेज-महाप्रबंधक टुडू

माही की गूंज, झाबुआ। गेल इंडिया लिमिटेड में एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन 24जून को सम्पन्न हुआ कार्यक्रम में महाप्रबंधक रामराय टुडू ।साहित्यकार डॉ रामशंकर चंचल।पूर्व प्राचार्य एच के पाठक और हिन्दी अधिकारी राहिग डामोर ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर बात रखते महाप्रबंधक टुडू ने कहा कि हिंदी आज पहले से अच्छी सुखद स्थति में फिर भी उसे उसका हक नहीं मिला जो मिलना चाहिए इसलिए हमे अपने सभी कार्य में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम उसे उसका हक दिला सके। इसी अवसर पर प्रख्यात साहित्यकार डॉ रामशंकर चंचल की ताजा कृति साहित्य का विमोचन महाप्रबंधक रामराय टुडू। पूर्व प्राचार्य एच के पाठक और हिन्दी अधिकारी आर डामोर और प्रेम रोहरा कर कमलों से सम्पन्न हुआ ।विमोचन करते महाप्रबंधक रामराय टुडू ने कहा कि हिंदी साहित्य में यह कृति साहित्य की अनुपम दस्तावेज है जिसमें कविताओं के साथ उनके सैकड़ों आयोजन के चित्र है जो डॉ रामशंकर चंचल की साहित्य साधना और सफलता को दर्शाते है ।अतिथि एच के पाठक ने कहा कि हिंदी साहित्य में यह कृति मूल्यवान है जो डॉ रामशंकर चंचल की अनुभूति सुखद अहसास को लेकर हमे अपने प्ररित करती है हमे अपने झबुआ पर गर्व होता है कि यहां महान साहित्यकार है। हिन्दी अधिकारी आर डामोर ने कहा कि साहित्य में यह कृति हिंदी साहित्य की वृद्धि करती है। जिसमे चंचल जी की अनुभूति सुखद ओर कलजयी है जो सदा प्रेरणा देती है में उन्हें बधाई देता हूं । संचालन और आभार जताया श्री आर डामोर ने किया।

पानी में डूबने से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता मंजूर

माही की गूंज, झाबुआ। मेघनगर तहसील के ग्राम तितरिया की 16 वर्षीय प्रियंका पिता कलसिंह की 6 मार्च 2020 को तालाब के पानी में डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर 4 लाख रूपए की आर्थिक सहमत मंजूर की गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पराग जैन द्वारा यह आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) की कण्डिका पांच के बिन्दु क्रमांक (2-क) के प्रावधानों के तहत मंजूर की गई है। मंजूर राशि मृतिका के भाई रमेश के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

कांग्रेस राज में रखी आंगनवाड़ी भर्ती की नींव को भाजपा सरकार ने सींचा - भाग -२

सूचना अधिकार में हुआ खुलासा, अपात्र ने नियुक्ति के लिए दिए फर्जी दस्तावेज

आंखों पर बंधी नोट की पट्टी ने कुछ नही देखने दिया जिम्मेदारों को, पात्र हो गई अपात्र

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

पिछले अंक में आंगनवाड़ी की भर्ती में फर्जी नियुक्ति करने का मामला पेटलावद विकास खण्ड के महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय के माध्यम से फर्जी भर्ती का मामला उजागर किया था। ग्राम पंचायत मोहनकोट के सेमलकुण्डिया के मेहम्मर फलिये के लिए निकली पोस्ट के लिए कुल सात महिलाओं ने आवेदन किया थे। जिसमें महिला बाल विकास द्वारा जारी सूची के अनुसार सेमलकुण्डिया के मेम्मर फलिये की निवासी संतोषी पति भवरसिंह मुनिया को सूची में प्रथम स्थान दिया गया था, लेकिन सूची अनुसार अपात्र घोषित हो चुकी अन्य महिला की नियुक्ति लेने-देनकर कर दी गई। जिस अपात्र महिला की नियुक्ति आदेश जारी किए गए उसके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों कि जानकारी धर्मेंद्र भूरिया निवासी सेमलकुण्डिया द्वारा सूचना के अधिकार में निकाली गई तो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया कि कैसे अपात्र को पात्र बनाने के लिए फर्जी कागज महिला के आवेदन के साथ लगाए गए। जिनको जानते देखते भी फर्जी नियुक्ति की गई। नियमों के अनुसार जिस फलिये में नियुक्ति होना है उस फलिये के आवेदक को प्राथमिकता होती हैं।

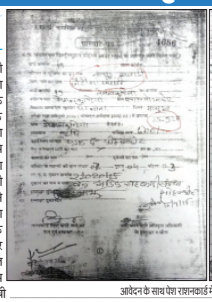

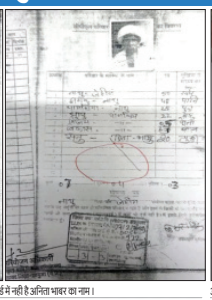

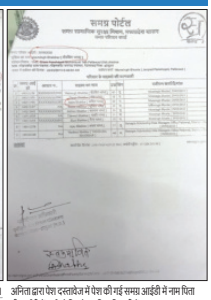

नियुक्ति के लिए पात्र घोषित संतोषी मुनिया सेमलकुण्डिया की ही फलिये की रहने वाली हैं। जबकी अपात्र घोषित हो चुकी अनिता भाभर मोरझारिया की रहने वाली है। वहीं यदि आवेदिका का नाम गरीब रेखा के राशनकार्ड में हो तो उसको भी पात्रता पहले होती हैं। सूचना अधिकार में प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार अनिता को सेमलकुण्डिया की निवासी बताने के लिए आवेदन के साथ अनिता के नाना नाथू खराड़ी का राशनकार्ड जिसका बीपीएल क्रमांक 22928 लगाया गया। जिसमें अनिता का नाम तक दर्ज नहीं है। अनिता द्वारा पेश किया गया निवासी प्रमाण पत्र में अपने आपको सेमलकुण्डिया का निवासी बताया गया। जबकि अनिता के पिता मोरझारिया में रहते है। समग्र आईडी में भी अनिता का नाम उसके पिता वीरसिंह भाभर के साथ दर्ज हैं। अनिता द्वारा पेश आधार कार्ड भी मोरझारिया उसके पिता के निवास पते पर बना हुआ है। नोकरी के लिए पेश दस्तावेज बिना नाम वाला नाना का राशनकार्ड और पिता के साथ आईडी पेश की गई। मोरझरिया के पते पर बने आधार कार्ड जैसी आवेदन में कई प्रकार की कमियां होने और उनको देखने के बाद भी अपात्र अनिता की नियुक्ति की गई। ऐसे कई दस्तावेज और भी है जिसे अनदेखा करके फर्जी नियुक्ति की गई हैं। अगले अंक में फर्जी शपथ पत्र सहित अन्य दस्तावेजों का खुलासा किया जाएगा।

आवेदन के साथ पेश राशनकार्ड में नही है अनिता भाबर का नाम।

अपने आप को निवासी प्रमाण पत्र में सेमलकुण्डिया निवासी बताया गया।

अनिता द्वारा पेश दस्तावेज में पेश की गई समग्र आईडी में नाम पिता की आईडी में दर्ज जो कि मोरझारिया निवासी हैं ।

रोड बना और नाली खा गए अब जनता परेशान

ग्राम जामली में जगह-जगह गंदगी का डेरा

माही की गूंज, जामली। जितेंद्र राठौर

जिस गांव को उज्ज्वल गांव का दर्जा प्राप्त हो, वहां पर ऐसी तस्वीर मिले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जी हां यह सच है! हम आपको सच के आइने से रूबरू करा रहे है। क्यूंकि सच कभी नहीं छुपता है। शासन की हर एक योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंचनी चाहिए लेकिन ग्राम पंचायत जामली में तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। यहां पंचायत द्वारा सीसी रोड बनाया गया, लेकिन साथ में नाली बनाना भूल गए। रोड बने दो से तीन साल बीत जाने के बावजूद अब तक नाली का निर्माण नहीं किया गया। जिसके कारण नाली का गन्दा पानी रोड पर बहता रहता है। गंदा पानी सड़क पर बहता देख वहां मिट्टी डाल दी गई। जिसके कारण गंदगी का अंबार लग जाता है। कच्ची नाली होने से गंदगी वहीं जमा रहती है। जिसके कारण रहवासियों को बीमारी का भय सताने लगा है। कई बार जिम्मेदारों को वार्ड के रहवासी अंबालाल भटेवरा, मनोहर मोठिया, रामचन्दर मोठिया, भमर सिंह, मागुसिंह आदि के द्वारा कहने के बावजूद जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे है। अंबालाल भटेवरा ने बताया कि नाली नहीं होने से मेरे घर में पानी भरा जाता है। बारिश के दिनों में भी यही हाल रहता है। जिसके कारण कई बार जहरीले जानवर भी आ जाते है। रात के समय पीछे जाने में डर लगने लगा है।

सीएम हेल्पलाइन से भी नहीं हुआ निराकरण

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बावजूद भी निराकरण नहीं हुआ। पंचायत के जिम्मेदारों के आश्वासन के बाद शिकायत कटवा दी जाती है। शिकायतकर्ता वार्ड क्रमांक 7 के विश्राम पाटीदार घर के सामने नाली नहीं होने से हो रही गंदगी को लेकर कई बार शिकायत कर चुके है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं आसपास के रहवासियों का भी कहना है कि बारिश के दिनों में यहां से निकलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी रास्ते से मंदिर को जाने वाले श्रद्धालु गंदगी से होकर गुजरने को मजबूर है। जिम्मेदार है कि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे है। समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बारिश के दिनों में रहवासियों के घरों में पानी भरना तय है।

मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का सुना संवाद

माही की गूंज, झाबुआ। विद्युत मण्डल के ग्रामीण क्षेत्र के प्रभारी पंकज डागी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिह चौहान के संवाद कार्यक्रम के तहत ग्राम छापरी तथा कालीदेवी ग्राम पंचाचत भवन पर संवाद सुनने का कार्यकम रखा गया। जिसमें विद्युत मण्डल संबधित योजनाओं और समस्या को लेकर आम जनता से संवाद किया। झाबुआ ग्रामीण विद्युत के अन्तर्गत 17 पंचायतों में 1हजार 272 उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री का संवाद सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके घरों के बिजली बिलों को आधे कर दिए है। मुख्यमंत्री ने वीडियों कॉन्फेंसिंग में आम जनता को विस्तृत जानकारी दी गई। जो उपभोक्ता संबल योजना में शामिल है तथा उनके बिल अधिकतम 100 रूपये आये है उन उपभोक्ताओं को अप्रेल, मई, जून माह में 100 रूपए तक बिल आने पर मात्र 50 रूपए बिल देना होगा। प्रदेश भर में 95 लाख परीवारों को फायदा होगा। उपभोक्तओं द्वारा अप्रेल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हे एक प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 10 हजार रूपए तथा उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम एक लाख रूपए होगी।

सरकार के दावे ढकोसले में तब्दील

जिम्मेदारों का कहना बीपीएल वर्ग के अलावा किसी को किसी प्रकार की कोई छूट नही

माही की गूंज, थांदला।

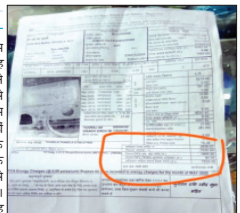

बिजली बिलों को लेकर एक बार फिर आम आदमी का गुस्सा चरम पर है। इस माह उपभोक्ताओं को दिए गए बेतहाशा बिलों ने उपभोक्ता की कमरतोड़ दी है। बीते तीन माह से कोरोना की मार झेल रहे आम उपभोक्ता पर काम धंधे बंद होने से दोहरी आर्थिक मार पड़ी है। वहीं भारी भरकम बिजली बिलो ने लोगों का सरकार के प्रति गुस्सा बड़ा दिया है। लोगो का कहना है कि सरकार हमारी मदद नहीं कर सकती है तो कम से कम जो हमारे पास बचा है वह तो नहीं छीने। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि लॉकडाउन के कारण आम जनता की परेशानी को देखते हुए बिजली बिलों में कमी की जाएगी। जिसे बड़े जोर-शोर से प्रचारित और प्रसारित किया गया था। किंतु इस माह विद्युत वितरण कंपनी ने जो बिल अपने उपभोक्ताओं को दिए हैं, वह मुख्यमंत्री की घोषणा को गलत साबित कर रहे है।

बीते कई महीनों से घर बैठकर अपनी जीविका जैसे-तैसे चलाने वाले छोटे दुकानदार व मध्यम वर्ग के लोग बड़े हुए बिजली बिलो से काफी परेशान है। बिजली विभाग के अधिकारियों के पास जब अपना दुखड़ा सुनाने जाते है तो अधिकारी कहते है अभी बिल जमा करना पड़ेगा हमारे पास कम करने के अधिकार भी नहीं है और आदेश भी नहीं है, लेकिन लोगों के सामने हजारों रूपए के बिल आज कहा से जमा करे यह समस्या खड़ी हो गई है। बिजली कंपनियां आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार से रियायत देने के मुड में नहीं है और सरकार के दावों को हवा में उड़ा रही है।

जिन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल 800 से 1200 आते थे उन्हें 4 से 6 हजार तक के बिल थमा गए हैं। लोग अभी लॉकडाउन से उपजी विपरीत आर्थिक परिस्थितियों से उबरने का प्रयास कर ही रहे थे कि इन भारी-भरकम राशि के बिजली बिलों ने आम आदमी की चिन्ता बढ़ा दी है। कई उपभोक्ताओं ने तो बताया कि बिजली बिल भरनें के लिए उन्हे कर्ज लेना पड़ेगा ऐसी स्थिति है। प्रधानमंत्री के आपदा को अवसर में बदलने की बात को बिजली कम्पनियों ने चरितार्थ करते हुए कोरोना जैसी आपदा झेल रहें आम आदमी के जेब खाली करने का अवसर नहीं छोड़ा है। जनरल स्टोर चलाने वाले वरदीचंद पंचाल ने बताया कि मेरा प्रतिमाह 1 हजार से 15 सौ रू का बिल आता था लेकिन इस माह का बिल 6 हजार रूपए का आया है। वैसे ही लॉकडाउन की वजह से धंधा बंद था हजारों रूपए के बिल कैसे भरेंगे। सेवानिवृत शिक्षक हिमसिंह डामर व शिक्षक देवचंद चरपोटा ने बताया कि इंदिरा ज्योति योजना तथा उससे पहले भी हमारे बिल कम ही आते थे किन्तु इस बार हजारों रूपए के बिल थमा दिए गए। बेतहाशा बिजली बिलों को लेकर सोशल मीडीया पर युवा वर्ग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है और बिजली बिलों की होली जलाने की बात भी कही जा रही है। युवा शंकर का कहना है कि सरकार ने लॉकडाउन में आम जनता की कोई सहायता नहीं की है और अपना खजाना भरने के लिए आम जनता की जेब खाली कर रही है।

माह अप्रेल के बिल औसत दिए गए थे, अप्रेल माह की शेष युनिट माह मई के बिलों में जुड़कर आने से ज्यादा राशि के बिल दिए जा रहे है। बीपीएल वर्ग के अलावा किसी भी प्रकार के घरेलु बिलों में कोई छुट नही है - **युवराज अवाया जेई वि वि क. थांदला।**

तू चल, मै आया तर्ज पर जिला प्रशासन के मौखिक आदेश या फिर हमाम मे सब नंगे

नहीं रूक रहा नगरपरिषद द्वारा बनाई जा रही अवैध दुकानों का निर्माण कार्य

माही की गूंज, थांदला।

नगर परिषद की अनियमितता की बात करना ही बेमानी होगा। प्रभारी सीएमओ अशोक चौहान की पहचान लापरवाही, अनियमितता और अनुशासन हीनता ही है। आज तक कभी किसी अधिकारी के मौखिक या लिखित आदेश की कभी भी परवाह नहीं की है। तब जाकर ये महाभ्रष्ट होने का तमगा पाया है। दो बार का निलंबन भी चौहान की उपलब्धि में शामिल है। हाल ही में नगरपरिषद लगभग 100 दुकान का निर्माण करने जा रही है, बिना नीलामी, बिना मुनादी किए, लेकिन चुपचाप नहीं खुले आम दुकानों की बुकिंग की है। दो से तीन लाख रुपया घूस ली गई है और दुकानें संबंधित लोगों को तय कर दी है। ऐसी भी खबरें चौराहे पर चर्चा में है। जिसकी पुष्टि हो रही है दुकानों के निर्माण से।

ये दुकानें नगरपरिषद चौराहा के पास नाले पर निर्माण की जा रही है, कुछ दुकानें पुराना पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने और महात्मा गांधी मार्ग पर तेजाजी मन्दिर के सामने प्रस्तावित हो कर निर्माण कार्य चालू है। नगरपरिषद पूर्व अध्यक्ष पति पूनमचन्द मिस्त्री के अनुसार यह निर्माण कार्य अवैध है। क्योंकि यह रोड सड़क प्राधिकरण की है। जिसके दोनों तरफ 15-15 फीट की जगह नियमानुसार छोड़ना अनिवार्य है तथा सड़क प्राधिकरण और रेवेन्यू का अनापत्ति प्रमाणपत्र भी आवश्यक होता है, लेकिन अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना मतलब अशोक चौहान का अहंकार गिर जाना।

पूनमचन्द मिस्त्री ने 4 जून को सड़क प्राधिकरण को इस संबंध में एक शिकायत पत्र मेल द्वारा भेजा। प्राधिकरण धार ने तैयारी में नगरपरिषद थांदला को काम बंद करने का निर्देश दिया। जिसकी परवाह अशोक चौहान करता भी नहीं है। साथ ही इस निर्देश की प्रतिलिपि कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को भी भेजी गई थी। जो रद्दी की टोकरी में जमा हो गया है। इस सम्बंध में कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को फिर से लगभग 15 दिन पूर्व शिकायत की गई। अबकी बार तहसीलदार ने आरआई से जांच करवा ली है, शिकायत सही पाई गई है, कार्यवाही होना बाकी है। एसडीएम साहब लम्बी छुट्टी पर चले गए है और कलेक्टर साहब ने कोई एक्शन लेने के नाम पर मौखिक रूप से तहसीलदार को कह दिया कि निर्माण कार्य बन्द करवाया जाए। ऐसे ही तहसीलदार ने प्रभारी सीएमओ को मौखिक निर्देशित किया कि निर्माण कार्य बन्द किया जाए। सभी के आदेश 'तू चल में आया' की तर्ज पर हवा हवाई हो गए। मौखिक आदेश का मतलब भी यही होता है, शिकायत कर्ता की शिकायत सही है, शिकायतकर्ता को सन्तोष करवाने के लिए मौखिक आदेश ऐसे ही जारी होते है। यह बात अशोक चौहान भी खूब समझता है। निर्माण कार्य में और तेजी लाते हुए अब निर्माण कार्य छत लेवल पर पहुंच रहा है। सेंटिंग ठोकी जा रही है। तहसीलदार को याद दिलाया तो तहसीलदार ने फिर से मौखिक रूप से सीएमओ को निर्देशित किया है कि कार्य बंद किया जाए। सीएमओ ने तहसीलदार को कहा है कि कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। नाली वाली खराब हो गई थी वही ठीक कर रहे है। तहसीलदार सीएमओ के कहने से अतिक्रमण हटाने के लिए तुरंत जाएगी लेकिन अवैध रूप से हो रही दुकान निर्माण को रोकने के लिए नहीं। जब सभी अधिकारी तू चल में आया की तर्ज पर काम करेंगे तो अशोक चौहान जैसे भ्रष्ट अधिकारी अपनी अवैध गतिविधि को कैसे रोकेंगे। या फिर यह मान लिया जाए कि हमाम में सब नंगे ही है। चौराहे की चर्चा के अनुसार बताया जाता है कि ढाई करोड़ रुपया इन दुकानों के आवंटन में घूस के रूप में अशोक चौहान ने वसूला है, थोड़ी-थोड़ी सेवाएं मौखिक आदेश करने वाले अधिकारियों को ऑफर कर दिया हो तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है।

जिला चिकित्सालय में चिकित्सको के नदारत होने से परेशान हुए मरीज

आधा दर्जन चिकित्सक रहे छुट्टी पर, खाली पड़ी रही ओपीडी

माही की गूंज, झाबुआ। जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का अंबार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक ओर जिला चिकित्सालय में मरिजों को ईलाज के लिए परेशान होना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों के छूट्टी पर जाने पर एक भी चिकित्सक ओपीडी में नहीं मिलता। वही सिनीयर चिकित्सकों की माने तो वे अपने टाईम के अनुसार ही ओपीडी छोड़ अपने घर की ओर रवाना हो जाते है। वहीं सिविल सर्जन को यह तक मालूम नहीं होता है कि ओपीडी में कोई चिकित्सक है या नहीं।

सोमवार 22 जून को जिला चिकित्सालय में करीब 11.30 से 12 बजे के भीतर एक भी चिकित्सक अपने ओपीडी स्थान पर नहीं बैठा था। जिस पर से कई मरिजों को ईलाज के लिए उल्टे पैर लौटकर अन्य निजी चिकित्सकों को दिखाना पड़ा। नगर के रिंकेश जैन अपनी माता जी को लेकर जिला चिकित्सालय दिखाने के लिए लाए थे, लेकिन जब चिकित्सक ही नहीं मिले तो उन्हे लौटना पड़ा। यदि कोई चिकित्सक छुट्टी पर जाता है तो उसके स्थान पर अन्य चिकित्सक की ड्यूटी लगती है, लेकिन सोमवार के दिन ओपीडी में मरिजों की भीड़ लगती है, इसके बावजूद भी चिकित्सक उपस्थित नहीं थे। ये आलम जिला चिकित्सालय में अब खुले आम कई बार देखा जा सकता है। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी है। जिसमें चिकित्सक अपने ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहते और वार्डबॉय उन्हे बुलाने के लिए जाते है। आखिर जिला चिकित्सालय में जहां एक ओर सिनियर चिकित्सकों ने अपनी मनमानी चला रखी है, वहीं दूसरी ओर जूनियर चिकित्सक भी अपनी मर्जी चला रहे है। आखिर सच भी है कि जब वरिष्ठ अधिकारी अपने साथ के सिनियर चिकित्सकों को ड्यूटी टाईम से पहले घर जाने से कुछ नहीं बोल पाते तो जूनियर आखिर क्यों सुनेंगे। जिला चिकित्सालय का पूरा बांस ही खोखला हो चुका है।

भाजपा ने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को याद किया

माही की गूंज, पेटलावद। पेटलावद भाजपा नगर मंडल द्वारा जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष हेमंत भट्ट ने वक्ता के रूप में उपस्थित कार्यकर्ताओं के बीच डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मुखर्जी का नारा था 'एक देश में दो विधान दो निशान दो प्रधान नहीं चलेगा'। राजेश यादव ने भी मुखर्जी के जीवन पर विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष कीर्तिश चानोदिया ने तथा आभार मंडल महामंत्री सोनू विश्वकर्मा ने माना। कार्यक्रम में संभागीय कार्यालय मंत्री अनंत पंवार, पार्षद शंकर राठौड़, संजय कहार, लाला चौधरी, जगदीश जाटव, महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी यादव, प्रवीण पवार, मुकेश परमार, बलदेवसिंह राठौर, आईटी सेल से कुंदन विश्वकर्मा उपस्थित थे।

आर्थिक सहायता स्वीकृत

माही की गूंज, झाबुआ। मेघनगर तहसील के ग्राम रामपुरा के 4 वर्षीय अभिजित पिता राजेश की 9 मई को तालाब के पीछे नाले में पानी की झीरी (पानी के गड्डे) के अन्दर पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पराग जैन द्वारा यह आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) की कण्डिका पांच के बिन्दु क्रमांक (2-क) के प्रावधानों के तहत स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि मृतक के पिता राजेश पिता कसन के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक आरटीआई एक्ट की उड़ा रहा धज्जियां

देश के कानून को ताक में रखकर, खुद का कानून चलाती ग्राम पंचायत

माही की गूंज, बामनिया। गौरव भंडारी

भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई ग्राम पंचायत बामनिया का स्वयंभू सरपंच और उसका चहेता रोजगार सहायक जो विगत तीन वर्षों से प्रभारी सचिव के पद पर कार्य कर रहा है कुछ सत्ताधारी नेताओं द्वारा बामनिया के विकास के लिए आई राशि में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और भाजपाई कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के विश्वास का खून भी किया है।

ऐसे ही वार्ड नं. 17 में पाइप लाइन डालने के दौरान कई लोगों के ओटले जानबूझकर तोड़े गए। कुछ रहवासियों को निजी नुकसान पहुंचाकर परेशान किया गया। वार्ड के निवासी सुरेश चोरड़िया भी पंचायत की हठ धर्मिता का शिकार हुए और पाइप लाइन के चले कार्य के दौरान वार्ड वासियों को मानसिक रूप से परेशान होना पड़ा। वहीं ईद का त्यौहार भी इस कार्य से प्रभावित हुआ। पंचायत के मनमाने व्यवहार और जानबूझकर परेशान करने की निती के कारण परेशान चोरड़िया ने शिकायत जनपद तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो परेशान सुरेशचंद्र ने बामनिया पंचायत के भ्रष्टों को सबक सिखाने की ठानी। सुरेश ने पंचायत में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न कार्यों की जानकारी मांगी। खिलाड़ी रोजगार सहायक ने आरटीआई अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए, एक माह बाद भी जानकारी नहीं दी। इसके विपरीत एक लिखित पत्र जारी कर सुरेशचंद्र चोरडिया को कहा कि एक बार में एक जानकारी ही आप मांग सकते हैं। रोजगार सहायक ने पत्र में कही भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किसी भी धारा का उल्लेख नहीं किया कि किस नियम, धारा तथा किस संशोधन के तहत प्रार्थी एक

रोजगार सहायक ने लिखित पत्र जारी कर सुरेशचंद्र चोरडिया को कहा कि एक बार में एक जानकारी ही आप मांग सकते हैं।

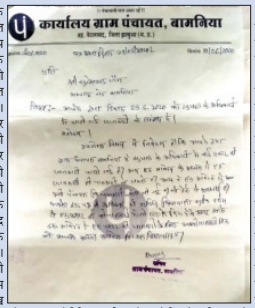

आवेदन में एक जानकारी मांग सकता है। केवल आम जनता को गुमराह करने और बामनिया पंचायत के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अपने आकाओं के इशारे पर इस तरह से बगैर नियमों का हवाला दिए पत्र जारी किया जाना रोजगार सहायक की योग्यता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि बामनिया जैसी बड़ी पंचायत केवल एक रोजगार सहायक के भरोसे चल रही है। जिसका मूल कार्य रोजगार गारंटी योजना के कार्यों को करवाने का है। अपना मूल कार्य करने के बजाए सचिव का कार्य कर रहे जीआरएस द्वारा इस वर्ष बामनिया में लॉकडाउन अवधि में कोई भी रोजगारमूलक सार्वजनिक कार्य नहीं चलाया गया और न ही किसी को मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार देने में रुचि दिखाई गई।

अपने मूल कर्तव्यों का पालन करने के बजाए रोजगार सहायक स्वयंभू सरपंच के हाथों की कठपुतली बनकर सूचना का अधिकार अधिनियम का मजाक बना रहा है। लेकिन वह अधिनियम की शक्ति के साथ खिलवाड़ करने में यह भूल गया कि इसमें प्रथम अपील और उसके ऊपर राज्य सूचना आयुक्त भी है। जो इसके जैसे लोग जो सूचना के अधिकार अधिनियम का मजाक उड़ाते हैं को दंडित करने का अधिकार भी रखते हैं।

इस संबंध में जनपद पंचायत पेटलावद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एनएस चौहान का कहना है कि ग्राम पंचायत बामनिया से सुरेशचंद्र चोरडिया द्वारा मेरे कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील की गई है। चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत बामनिया को निर्देशित किया गया है। जानकारी नहीं देने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कारवाई की जाएगी।

कोदली पंचायत में फर्जी तरीके से एक ही जगह पर दो सीसी रोड बना दिए गए

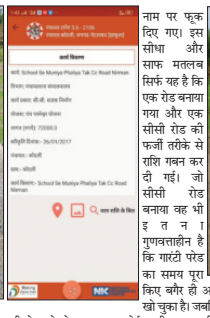

माही की गूंज, पेटलावद।

जैसे-जैसे गूंज की कलम ग्राम पंचायतों में फैले भ्रष्टाचार उजागर कर रही हैं। एक के बाद एक मामले ग्राम पंचायतों के सामने आ रहे है। ग्राम पंचायतों की अब इतनी शिकायतें गूंज के पास आ गई हैं कि रोज के रोज पूरे अखबार के पन्ने भी इनके भ्रष्टाचार से रंगे जाए तो अखबार छोटा पड़ जाए। यहां ग्राम पंचायत कोदली में एक ही रोड को दो बार बनाने का मामला सामने आया है। और रोड भी ऐसा की साल दो साल में ही अपना अस्तित्व खो चुका हैं। यहां कोदली ग्राम पंचायत के मालपाड़ा फलिया में पंचायत द्वारा एक ही जगह पर दो रोड बना दिए गए। ग्राम पंचायत ने पहले 2016 में ढाई लाख की लागत से स्कूल से मुनिया फलिये तक बनाया और फिर इस रोड पर वर्ष 2017 में 72,000 रोड बनाने के नाम पर फूक दिए गए। इस सीधा और साफ मतलब सिर्फ यह है कि एक रोड बनाया गया और एक सीसी रोड की फर्जी तरीके से राशि गबन कर दी गई। जो सीसी रोड बनाया वह भी इतना गुणवत्ताहीन है कि गारंटी परेड का समय पूरा किए बगैर ही अस्तित्व खो चुका है। जबकि रोड पर कोई भारी वाहन भी नहीं गुजरते। इसके बाद भी रोड पूरी तरह समाप्त हो चुका है। सीसी रोड निर्माण को बने लगभग 03 साल भी नही हुए और रोड उखड़ कर गड्ढों में तबदील हो गया है, गिट्टी अलग हो गई। विकासखण्ड की अन्य पंचायत की तरह कोदली पंचायत में भी इस तरह के काले कारनामों को सरपंच सचिव ने अंजाम दे रखा है।

गरीब की जमीन पर लालची नगर परिषद की काली नजर

गरीब को हटाकर, मार्केट बनाने की योजना, सांसद के पत्र को मजाक बनाकर उड़ाया हवा में

माही की गूंज, पेटलावद।

कांग्रेस सरकार में चली अतिक्रमण मुहिम में कई लोगों को बेघर और बेरोजगार करने वाली नगर परिषद में बैठे दलालों और भूमाफिया की काली नजर अब गरीब की बेशकीमती जमीन पर पड़ गई है। इसलिये भूमि को हथियाने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर येन-केन प्रकारेण जमीन कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि पेटलावद के रायपुरिया रोड पर बना बरवेटा का बीज का कारखाना पेटलावद पुलिस थाने की भूमि में बना हुआ पाया गया हैं। वहीं थांदला रोड़ पर बने प्रेमसागर गार्डन में शासकीय नाले की भूमि को अब तक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया गया। उल्टा लेनदेन कर गॉर्डन के लिए शासकीय भूमि में रास्ता दे दिया गया। बरवेट रोड पर बरवेटा द्वारा काटी गई फर्जी कॉलोनी पर अतिक्रमण हटाने गई राजस्व की टीम बेईज्जत होकर उल्टे पांव लौट चुकी है। ऑफ दी रेकॉर्ड नगर परिषद में दर्ज कांजी हाउस आज निजी हाथों में चला गया हैं। ऐसे कई गंभीर मामले अतिक्रमण मुहिम के दौरान सामने आए, जिन्हें कहीं नोटो तो कहीं न्यायालय के नाम पर फाइलों में दबा दिया गया। आज भी अथा संपत्ति के मालिक शासकीय भूमि पर कब्जा करके बैठे हैं, लेकिन नगर परिषद की नजर केवल स्टेट बैंक के पास की भूमि पर है। जहाँ एक गरीब परिवार प्रशासन की दबंगई के कारण बिना छत के रहने पर मजबूर हैं, लेकिन नगर परिषद को ये भी रास नहीं आ रहा है और अब यहां नगर के करोड़पति सेठों के लिए मार्केट बनाने की योजना बना रही है। जिसके लिए बार -बार पीड़ित

नगर परिषद अध्यक्ष अपने अमले के साथ गरीब परिवार पर भूमि से हटने के लिए दबाव डालते हुए।

को परेशान किया जा रहा है। वैसे तो शासन का नियम है कि यदि किसी शासकीय भूमि पर लम्बे समय से कब्जा है तो उसे पट्टे और मालिकाना हक का प्रावधान हैं। ऐसे कई वचिंत और गरीब परिवारों को पट्टा दिया जाना है, लेकिन पेटलावद में ऐसे एक नहीं कई उदाहरण मिल जाएंगा जिनके पास लाखों की सम्प्पत्ति होने के बाद भी सरकारी भूमि पर लीज और पट्टे करवा कर सरकार की भूमि गलत तरीके से हथियाकर आलीशान बंगले ओर मार्केट बना दिए। वहीं आज एक गरीब परिवार छत के लिए मोहताज हो गया। पेटलावद निवासी राधाकिशन गुर्जर का परिवार लगभग 40 वर्षों से अधिक समय पर सर्वे नबर 1105 पर रहता आया है। पूर्व में भी अतिक्रमण बताकर हटाया गया था, लेकिन न्यायालय में जाने के उक्त भूमि का पट्टा राजीव गांधी आवास योजना में पट्टा दिया गया। नगर परिषद में 1982 तक टेक्स के पैसे भी जमा करवाए गए, लेकिन भ्रष्टों ने अपने काले कारनामें छुपाने के लिए नगर परिषद के पुराने रेकार्ड गायब कर दिए और अब नगर परिषद हमारे पास रेकॉर्ड नहीं होने का हवाला देकर राधाकिशन को भूमि से हटा रही है। अतिक्रमण मुहिम के दौरान नगर परिषद में बैठे कुछ भ्रष्टों की नजर इस भूमि पर ऐसी पड़ी कि यहाँ एक बार तो बनी चद्दर पोश दुकानों को अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया और फिर 15 दिन बाद पूरे मकान की योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया।

राधाकिशन को पट्टा देने के लिए सांसद को लिखा गया पत्र।

अब लॉकडाउन से स्थिति सामान्य होने के बाद फिर से नगर परिषद दुकानें बनाने के नाम पर टूटा हुआ आशियाना भी छीनना चाहती है। राधाकिशन ने अनुविभागीय अधिकारी और नगर परिषद में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई हैं कि भूमि पर वर्षों से कब्जा होकर उक्त भूमि का पट्टा दिया गया हैं।

सांसद के पत्र को हवा में उड़ाया

नगर परिषद और सांसद के बीच चल रही आपसी खींचतान कोई नई नहीं है अतिक्रमण मुहिम में राधाकिशन का मकान तोड़ने के बाद राधाकिशन के परिवार ने सांसद गुमानसिह डामोर को गुहार लगाई थी। जिसके बाद 27 फरवरी 2020 को एक पत्र अनुविभागीय अधिकारी को लिख कर राधाकिशन के परिवार को राजीव गांधी आश्रय योजना में पट्टा देने को कहा था। उक्त पत्र के माध्यम से राधाकिशन नगर परिषद में भी गुहार लगा चुके हैं लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। गत दिनों उक्त भूमि की नपती के लिए पहुँचे नगर परिषद के अमले जिसमें अध्यक्ष मनोहर लाल भटेवरा भी मौजूद थे। राधाकिशन के पास रखे कागज और सांसद का पत्र भी दिखाया लेकिन अध्यक्ष द्वारा सांसद के पत्र को हवा में उड़ा कर अनदेखा कर कह दिया सांसद क्या करे यहाँ हमारा राज हैं। कोरोना संकट में लॉकडाउन और बीमारी से जूझ रहे बेरोजगार गरीब परिवार के साथ हो रहे व्यवहार को देखकर शासकीय व्यवस्था और नगर परिषद पर थू-थू कर रहे हैं।

पृष्ठ 1 से शेष...

कालीघाटी और बाछीखेड़ा में मनरेगा तालाब में चली जेसीबी

भ्रष्ट उपयंत्री अहिरवार का मायाजाल, रात के अंधेरे में मजदूरों के हक पर डाला डाका

मामला नंबर -2

कल रात के अंधेरे में लगभग साढ़े सात लाख के तालाब को रातों-रात जेसीबी मशीनों से कार्य को पूर्ण कर ग्राम पंचायत के मजदूरों का रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। पंचायत रोजगार सहायक करणसिंह खड़िया, सरपंच नानूराम मुनिया, सचिव खुशाल वसुनिया द्वारा सभी अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। उपयंत्री अहिरवार की सेटिंग से पंचायतों के कामों को कागज पर ही निपटाया जा रहा है। गांव के ही अमृतलाल भाभर द्वारा रात में ही जोस्का वाली खाली निस्तार तालाब में जेसीबी चलने सूचना देने पर भी मशीन से चल रहे कार्य को नहीं रोक गया और रात के अंधेरे तालाब बना दिया गया। साफ- साफ देखने में आ रहा है कि उपयंत्री अहिरवार की भी मिलीभगत से लगातार भारी मशीनों से काम हो रहे है। ग्राम पंचायत बाछिखेड़ा के अमृतलाल भाभर के द्वारा उपयंत्री को रात को ही सूचना कर दी गई थी जिसके बाद भी जेसीबी नहीं रोक जाना इनकी कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि उपयंत्री अहिरवार के कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग और जेसीबी की वीडियो सहित फिर शिकायत करेंगे। मामले की जांच के लिए पहुंचे अधिकारी ग्राम पंचायत और उपयंत्री को बचाते नजर आए। गोलमोल पंचनामा तैयार कर उसमें बताया गया कि तालाब से लगभग पचास फीट दूर बने कुएं पर जेसीबी चलाई हैं। जिससे मौके पर मौजूद ग्रामीण भड़क गए और लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए पंचनामा तक फाड़ दिया। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अधिकारी सरपंच-सचिव और उपयंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे है। जिसके बाद मनरेगा के एसडीओ भोसले ने नया पंचनामा तैयार किया। उसमें भी तालाब पर चली जेसीबी साफ दिखने के बाद भी कुंए पर जेसीबी चलना कुएं मालिक के बयान के हिसाब से लिखा गया। जबकि मौके पर कुएं के आसपास जेसीबी चलने के कोई निशान नहीं थे। कुंआ भी पानी से भरा हुआ था, लेकिन अधिकारी मामले की गली निकालते ही दिखे। जिस प्रकार से पंचनामें तैयार किए जा रहे है उससे यह स्पष्ट है कि भ्रष्टों को बचा लिया जाएगा।

चौकी पहुंचा मामला, एक-दूसरे पर लगा रहे आरोप

बाछीखेड़ा का मामला इस कदर बड़ गया कि पूरा मामला चौकी सारंगी पहुँच गया। मिली जानकारी के अनुसार बाछीखेड़ा के सरपंच-सचिव ने अपने ही रोजगार सहायक करणसिंह पर बिना जानकारी के तालाब पर जेसीबी चलाने का आरोप लगाया। चौकी प्रभारी उषा अलावा से मामले की पुष्टि का प्रयास किया तो कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन चौकी में पदस्थ एक हेडसाब सहायक ने सचिव को चौकी पर बैठा लाए। जहां सहायक सचिव खुद एक आवेदन हाथ में लेकर खड़ा था। जिसने गांव के ही कुछ लोगों पर तालाब पर जेसीबी चलाकर फंसाने के आरोप लगाया गया था। सरपंच-सचिव और सहायक सचिव के आमने-सामने होने के बाद चौकी पर भंजगड़ी की परंपरा शुरू हो गई। फिलहाल बिना कार्यवाही के सभी को रवाना कर दिया गया। बताया जा रहा है पुलिस ने सहायक सचिव का आवेदन तक नहीं लिया। दोनों मामले में अधिकारियों की ओर से पुलिस रिपोर्ट दर्ज होनी थी, लेकिन अपनी गर्दन बचाने के लिए अधिकारियों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। वहीं ग्राम पंचायत की ओर से चौकी पर पहुंचे मामले को भी अब बहार ही निपटाया जा रहा है।

ग्राम पंचायत बाछीखेड़ा में जांच करने पहुंचे अधिकारियों का ग्रामीणों ने किया घेराव।

मामला चौकी पर पहुंचे के बाद हेडसाब सहायक सचिव को चौकी पर ले आए लेकिन उसका आवेदन नहीं लिया।

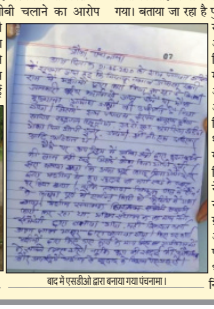

बाद में एसडीओ द्वारा बनाया गया पंचनामा।

15 साल तक भाजपा शासनकाल में जीवित रही अतिथि विद्वान व्यवस्था

उच्च योग्यताधारी का होता रहा भविष्य चौपट, तीन लोग अब तक झुल चुके है फांसी के फंदे पर

माही की गूंज, झाबुआ। अतिथि विद्वान व्यवस्था का जन्म जरूर दिग्विजयसिंह के शासनकाल में 2002 में हुआ था। लेंकिन नेट, स्लेट, एमफिल, पीएचडी धारक युवाओं का भविष्य चौपट करने वाली प्रथा को 15 साल 3 माह के सबसे लम्बे समय तक जीवित रखने का कार्य बीजेपी सरकार ने ही किया हैं। इस बीच 15 माह 6 दिन की कमलनाथ सरकार ने इन्हे वचन-पत्र में नियमित करने का स्थान देकर भी शिवराज सरकार में हुई भर्ती से चयनितो को दिसंबर 2019 में नियुक्ति दे दी। जिससे 2000 अतिथि विद्वान फॉलेन आउट होने से परेशान हैं। कोई भी प्लान अधिकतम 5 वर्ष के लिए बनता हैं, परंतु इस व्यवस्था ने तो सरकार को स्वार्थी बना दिया। 25 वर्ष के युवा से 50 वर्ष के व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करवाना कहां का न्याय है। इन्होने अपनी जीवन रक्षा के लिए छिंदवाडा से लेकर भोपाल तक 4 माह आंदोलन किया था। लेंकिन पूर्व मंत्री जीतु पटवारी की झूठ ने इनके करियर को आज तक उलझाकर रख दिया हैं। अब प्रतिदिन शिवराज सरकार से गुहार लगा रहें हैं, परंतु न तो चयन सूची जारी हुई, न ही नियमितीकरण हुआ हैं। जबकि धरने के समय बडा जोर देकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने समर्थन किया था। वहीं आर्थिक संकट, बीमारी और नौकरी छीन जाने के कारण अब तक डॉ. राजेश चढार, डॉ. विजय लहासे, डॉ. शमी खरे व मासूम काव्यांश की मौत हो चुकी है। इनके अलावा ऐसे ही कारणो से संजयकुमार, डॉ. अजय त्रिपाठी और सुनील चौहान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेरोजगारी का डर इनके परिवारो पर भी मंडरा रहा है। अतिथि विद्वान मोर्चा के मीडिया प्रभारी शंकरलाल खरवाडिया ने बताया कि, सीएम शिवराजसिंह चौहान और उनके मंत्रियो, अधिकारियों ने मार्च से आज तक केवल झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया हैं। चयन सूची जारी करना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया है। अधिकारियों ने जबरन इसे रोक रखा है।

संपादकीय

सेना को खुली छूट देने से ही मिलेगा दुश्मनों को सही जवाब

भारत सरकार ने सैनिकों को गोली चलाने की खुली छूट दी है। अब वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीनी सैनिकों को कोई हिमाकत करने से पहले चार बार सोचना पड़ेगा। हमारे सैनिक अब द्विपक्षीय संधियों और समझौतों की जकड़न से भी मुक्त होंगे। यदि हालात आक्रामक हैं और दुश्मन हथियारों का इस्तेमाल करता है, तो यह आकलन सैनिकों को ही करना है और फील्ड कमांडर के इशारे पर वे फायरिंग खोल सकेंगे। हालांकि यह अंतिम विकल्प के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। बेशक इससे भारत-चीन के बीच तनाव और संभावित टकराव के आसार पुख्ता होंगे, लेकिन दुश्मन की हरकतों और चालों का 'यथोचित जवाब' इसी भाषा में ही दिया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ लंबे विमर्श के बाद यह निर्णय लिया। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मुहर लगा दी। इस खुली छूट के साथ-साथ एक आपातकालीन कोष तैयार करने का भी फैसला लिया गया है। उसके तहत सेना प्रमुख 500 करोड़ रुपए तक के घातक हथियार तुरंत खरीद सकेंगे और उन्हें सरकार की लंबी प्रक्रिया की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। मोदी सरकार के ये फैसले भी ऐतिहासिक और लीक से हटकर हैं, क्योंकि ये 1996 और 2005 के भारत-चीन समझौतों का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं। इससे दोनों पक्षों के सैनिकों में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। अभी तक जो झड़प हाथापाई और धक्का-मुक्की तक सीमित थी, अब हिंसक और हत्यारी ही होगी। एलएसी पर 15-16 जून की शाम में जो टकराव हुआ था, उसका तनाव अब भी बरकरार है। कुछ खुलासे किए गए हैं, जिनसे टकराव अब एकतरफा नहीं लगता। हमारी सेना के उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के मुताबिक भारत के सैनिकों ने चीन के 56 सैनिकों को मारा था। चीनी सैनिकों के शव गलवान घाटी में इधर-उधर मिले थे, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने चीनी पक्ष को सौंप दिया। लड़ाई की भी एक नैतिकता होती है। इसके अलावा, चीनी सेना के एक कर्नल और करीब 15 सैनिकों को बंधक भी बनाया गया था। बीते रविवार उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन अब तक चीन को एहसास हो गया होगा कि सामने भारत के पेशेवर सैनिक हैं। इसके बावजूद चीनी सैनिक एलएसी के पास डेरा डाले हैं। हमारे सैनिक भी तैनात हैं। लड़ाकू विमानों की गर्जनाएं खौफ पैदा कर रही हैं। बहरहाल द्विपक्षीय संधियों और समझौतों का महत्त्व तभी तक है, जब तक युद्ध के आसार न बनें। समझौते किए गए थे कि एलएसी के दो किलोमीटर के दायरे में गोलीबारी नहीं होगी। 10 किलोमीटर के इलाके में कोई हवाई उड़ान नहीं होगी। एलएसी पर परमाणु विस्फोट नहीं किया जाएगा। रात में गश्त भी नहीं की जाएगी। कोई स्थायी ढांचा भी निर्मित नहीं किया जाएगा। एलएसी पर वाहनों की संख्या भी सीमित होगी। यदि गोली और दूसरे आग्नेय अस्त्र चलाने की छूट देने की नौबत आई है, तो उसके लिए चीन जिम्मेदार है। अभी तक दोनों देशों के सैनिकों के बीच गोली नहीं चली थी, लेकिन जिन आदिम हथियारों से और घात लगाकर चीन ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया, उसके जरिए चीन ने ही द्विपक्षीय समझौते को खारिज किया। लिहाजा समझौता बेमानी हो गया और भारत को भी गोली चलाने का फैसला लेना पड़ा। चीन की सीमाएं 23 देशों से लगती हैं। ऐसा क्यों है कि सभी देशों के साथ उसके विवाद हैं, रिश्ते खराब हैं? क्योंकि चीन फितरत से ही कब्जेबाज और विस्तारवादी है। कमोबेश भारत के संदर्भ में उसे याद रखना चाहिए कि भारत की सेना 1962 वाली नहीं, आज 2020 वाली है, लिहाजा पलटजवाब भी उतना ही आक्रामक होगा। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि लेह, श्रीनगर और आसपास के इलाकों में हमारे भी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हैं, आईटीबीपी के 2000 अतिरिक्त जवान भी वहां बुलाए गए हैं, सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, घर गए सैनिकों को वापस मोर्चों पर बुलाया जा रहा है और सिर्फ 72 घंटे में हमने एक पुल बना दिया है। जाहिर है कि हालात सामान्य नहीं हैं। इस निर्णय की प्रतिक्रिया पर चीन धमकी-सी दे रहा है कि भारत को अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब जो भी होगा, लेकिन चीन को चीन के अंदाज में ही जवाब देना सही रणनीति है।

काम की बात

इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नही आता मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों-जन्मों तक काम आता है।

एक सलाह

लफ्जों के दांत नहीं होते, पर ये काट लेते है। दीवारें खड़े किए बगैर बांट देते है।

राजनीतिक द्वंदः 'आत्मनिर्भर' व 'आत्मसमर्पण' के बीच

ओमप्रकाश मेहता
लेखक

भारत की सीमा पर चीन ने चाहे अघोषित युद्ध छेड़ रखा हो, किंतु भारत में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस के बीच चीन को लेकर ही घोषित युद्ध छिड़ गया है, पक्ष-विपक्ष के बीच यह वाक-युद्ध 'आत्मनिर्भर' व 'आत्मसमर्पण' के हथियारों से लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जहां चीन को हराने के लिए 'आत्मनिर्भरता' का नारा दिया, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए चीन के संदर्भ में 'सरेण्डर' (आत्मसमर्पण) शब्द का उपयोग किया, यद्यपि जहां तक मोदी के लिए 'सरेण्डर' या 'आत्मसमर्पण' के उपयोग का सवाल है, वे सही में 'आत्मसमर्पित' है, किंतु अंतर सिर्फ इतना है कि वे देश की सेवा के प्रति आत्मसमर्पित है, चीन के सामने नहीं, और इसी कारण अंग्रेजी का यह 'सरेण्डर' शब्द मोदी जी के लिए गाली बन गया और भाजपा ने राहुल के लिए तलवारें तान ली।

पिछले एक-दो दिनों के इसी राजनीतिक घटनाक्रम व उसके कारणों पर सूक्ष्म नजर डाले तो इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी या उनकी माँ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी को व्यक्तिशा इसलिए दोषी नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें इन माँ-बेटे का दोष नहीं बल्कि दोष सही राजनीतिक प्रशिक्षण व संस्कारों के अभाव का है। आज की कांग्रेस की दुरावस्था पर यदि गंभीर चिंतन किया जाए तो इसके लिए दोषी इसमें राजनीतिक परिपक्वता व संस्कार का अभाव ही है, कांग्रेस की नई पीढ़ी के प्रमुख सदस्य राहुल गांधी या पूर्व कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों का ही राजनीति में प्रवेश विरासत के कारण मिला, इंदिरा जी की हत्या के समय तो राहुल मात्र चौदह वर्ष के थे, इसलिए उनसे राजनीति का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और इनके पिताजी स्व. राजीव गांधी को भी आनन-फानन में पॉयलट की नौकरी छोड़कर राजनीतिक अपरिपक्वता की स्थिति में प्रधानमंत्री बनना पड़ा था, किंतु चूंकि उन्होंने पॉयलटी के साथ अपनी माँ का राजनीतिक करतब भी करीब से देखा था, इसलिए उन्होंने पांच साल प्रधानमंत्री के रूप में ठीक से काम किया, किंतु उनकी पत्नी और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बहू रहते हुए अपनी सास से राजनीति का पाठ पढ़ने में कोई रूचि नहीं दिखाई, इसलिए वे राजनीतिक दृष्टि से अपरिपक्व रही और राजीव की हत्या के बाद उन्हें पति की विरासत के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष बनना पड़ा, यद्यपि उन्होंने अध्यक्ष के रूप में दस साल कांग्रेस की सरकार चलाई, जिसके कई विवाद आज भी उभर कर ऊपर आ जाते है, फिर जब अपनी ममता व महत्वकांक्षा के तहत राहुल को अध्यक्ष बनाया तो वे पार्टी के लिए यथोचित उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाए और फलतः सोनिया को अध्यक्ष पद वापस लेना पड़ा। यही स्थिति कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी रही, उनकी भी राजनीतिक दीक्षा पूरी नही हो पाई और माधवराव जी चले गए, यदि माधवराव जी उन्हें राजनीति का सिर्फ एक पाठ (अपने आस-पास वालों से कैसे निपटना) ठीक से पढ़ा पाते तो आज ज्योतिरादित्य को कांग्रेस छोड़ने को मजबूर नहीं होना पड़ता।

...तो कुल मिलाकर यही मान लिया जाना चाहिये कि देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृष्य में कांग्रेस के धीरे-धीरे लोप होने के पीछे मोदी जी का कोई करिश्मा या चमत्कार नहीं है, बल्कि कांग्रेस स्वयं अपनी नादानी और बचकानी हरकतों से गिर रही है, वर्ना यदि इंदिरा जी द्वारा प्रशिक्षित संजय गांधी होते तो आज कांग्रेस का चाल-चरित्र और चेहरा अलग ही होता और आजादी के बाद से इस देश में दो ही दल मुख्य रहे पूर्व जनसंघ या वर्तमान भाजपा तथा कांग्रेस, और कांग्रेस चूंकि संक्रमण के दौर से गुजर रही है और कोई क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल बन नही पाया इसीलिए आज भाजपा की ''तूती'' बोल रही है।

अब यदि फिर वही सवाल उठाया जाता है कि पचास वर्षिय राहुल को सत्तर वर्षिय नरेन्द्र मोदी को 'सरेण्डर' की राजनीतिक गाली नही देनी थी तो इसके लिए राहुल का नहीं बल्कि उनमें संस्कारों का अभाव दोषी है, यदि संस्कारों का अभाव नहीं होता तो देश के मौजूदा हालातों में सभी के साथ होने की जगह वे अपनी ढपली अलग क्यों बजाते? अरे..... जब वर्तमान हालातों में ममता बैनर्जी जैसी घोर मोदी विरोधी मोदी की सरकार की सहयोगी बनी हुई है तो संसद के दरबार में खुलेआम मोदी के गले लगने (बकौल मोदी गले पड़ने) वाले राहुल अब अचानक वाचाल कैसे बन गए? और कांग्रेस व उसके आकाओं का मौजूदा रवैया ऐसे ही जारी रहा तो फिर कांग्रेस की नैया को रानीति के मझधार में डूबने से कोई नहीं बचा सकता।

कोरोना काल के मुनाफेखोर

अमरीक

कोरोना वायरस मनुष्यता और सभ्यता को इस वक्त बेहद नागवार चुनौती दे रहा है। शेष दुनिया के साथ-साथ हमारा देश भी इससे जूझ रहा है। पंजाब में भी कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। कोरोना बेशुमार जनद्रोही मुनाफाखोरों के लिए धंधेबाजी का साधन बन गया है। पंजाब ही नहीं बल्कि कोरोनाग्रस्त कई दूसरे राज्यों में भी हालात कमोबेश एक सरीखे हैं।

इस संकट ने सबसे ज्यादा जिस संस्था का इकबाल तार-तार किया, वह चिकित्सा जगत है। कोरोना वायरस फैलते ही छोटे-बड़े तमाम अस्पतालों ने ओपीडी बंद कर दीं। जिनकी जारी रहीं उनमें परामर्श फीस में एकाएक चार गुना की बढ़ोतरी हो गई। आपातसेवा वार्डों में श्सेवाश् की बजाए निर्लज्ज खुली लूट होने लगी। सीधे दस प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी गई। गाड़ी और रुतबा देखकर इलाज होने लगा। लुधियाना के एक बड़े अस्पताल का संचालक-डॉक्टर कुख्यात है कि वह सीसीटीवी कैमरों के जरिए पार्किंग पर निगाह रखता है ताकि पता चल सके कि आने वाला मरीज किस स्टैंडर्ड यानी कितनी महंगी गाड़ी में आया है। मतलब साफकि हैसियत देखकर लूटा जाता है! सबसे पहले कोरोना टेस्ट करवाना अपरिहार्य है। इसके लिए मनमर्जी कीमत वसूल की जाती है। बेशक सरकार ने टेस्ट के लिए तयशुदा शुल्क तय किया हुआ है लेकिन ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल सरकारी एडवाइजरी की ओर से पीठ किए हुए हैं। कम से कम पंजाब में तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि मामूली खांसी-जुकाम और दमे के मरीजों को रिपोर्ट आने तक लूटा जाता रहा। जिन्हें पॉजिटिव बताकर सिविल अस्पताल या आइसोलेशन वार्ड में भेजने की सिफारिश की गई, दूसरी लैब अथवा अस्पताल में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव निकली। मेडिकल भाषा के इस पॉजिटिव-नेगेटिव में बहुतेरे लोगों पर श्कोरोनाश् पीड़ित का ठप्पा लगा और उन्हें सामाजिक तौर पर बहिष्कृत होने का दंश झेलना पड़ा। यह सब आज भी जारी है।

सरकारी अस्पताल कोरोना संदिग्धों के लिए यातना शिविर बन गए हैं और प्राइवेट अस्पतालों में उस बीमारी (कोरोना वायरस) के इलाज के लिए छह से सात लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जिसकी प्रमाणिक दवाई दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। जब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बड़े अस्पतालों में कोरोना के संदेह में लोग जाने लगे तो अस्पतालों और लैब मालिकों की मिलीभगत भी सामने आने लगी। खुलासा हुआ कि कई जगह निजी अस्पतालों के इशारे पर मामूली अलामत के शिकार को कारोना पॉजिटिव बता दिया गया। गोया वह बीमारी का नहीं डॉक्टरों का शिकारश् बन गया! बीते दिनों अमृतसर की एक बड़ी लैब पर विजिलेंस ने शिकायतें मिलने के बाद छापा डाला। इस लैब से रेड जोन में आए अमृतसर के हजारों लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाए थे। इस लैब में पॉजिटिव-नेगेटिव का गलीज खेल चलता रहा। अब यह लैब सील है, जिसपर लोगों को अंधा भरोसा था। गुरु की नगरी में यह पाप होता रहा और यकीनन कई शहरों में हो रहा होगा। क्या चिकित्सा जगत की पवित्रता अब अतीत की बात है? सब जगह एक और दिक्कत है। डॉक्टर मरीजों को कई फुट की दूरी से जांचते हैं। आपकी जेब अगर भारी नहीं है तो रक्तचाप तथा शुगर चेक करवाने में समस्या आएगी। अलबत्ता मेडिकल हॉल वाला यह काम जरूर कर देगा। अपने अंदाजे से दवाइयां भी दे देगा।

कोरोना फैलने के बाद श्रमिक तबका पूरी तरह टूट गया। मजदूरों का देशव्यापी पलायन शुरू हुआ। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच मजदूर पैदल अपने मूल राज्यों की ओर कूच करने लगे। मुनाफाखोरों ने जमकर उन्हें लूटा। कौड़ियों के दाम पर उनका सामान, साइकिल, मोबाइल, पंखे और बर्तन हथिया लिए। राशन की दुकानों पर दोगुने दामों पर उन्हें सामान बेचा गया। बेशुमार मजदूर श्कबूतरबाजीश् यानी गैर कानूनी तौर पर मिलीभगत से चलने वाली ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने घर-गांव लौटे। इस कवायद में उन्होंने बरसों की कमाई झटके में गंवा दी। मुनाफाखोरों ने उन्हें इस कदर बर्बाद कर दिया कि खाने तक को कुछ नहीं बचा। लूट किस वर्ग की नहीं हो रही? श्पीछे से कुछ आ नहीं रहाश् यह कहकर सामान अब भी बेहद महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। यहां तक कि जीवनरक्षक दवाइयां भी। बंद स्कूल भी विद्यार्थी बच्चों के अभिभावकों से मोटी फीस बटोरने की कोशिश में हैं। सरकार की हजार सख्ती के बावजूद।

कविता की पंक्ति- श्आ दोस्त चंदा करें अकाल पड़ा है धंधा करेंश् की तर्ज पर कई तथाकथित समाजसेवियों ने खूब चंदा किया जो उनकी निजी तिजोरियों में बंद है। कई जगह सरकारी-गैरसरकारी राशन वाजिब जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा। मुनाफाखोरों ने बीच रास्ते उसे हड़प लिया। तो कोरोना वायरस की मुनाफे की मंडी में मुनाफाखोर खूब पूजा कर रहे हैं और रोज कामना करते हैं कि यह जानलेवा संक्रमण जाए नहीं! धिक्कार है...!!

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

गलवान पर मोदी दुविधा खत्म करें

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

गलवान घाटी में हुए हत्याकांड पर विरोधी नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे आरोप लगा रहे हैं तो चीनी अखबार उनके संयम की तारीफें पेल रहे हैं। कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी ने कहा है कि यह 'नरेन्दर' मोदी नहीं, 'सरेन्डर' मोदी है याने मोदी ने चीनियों के आगे आत्म-समर्पण कर दिया है। मोदी ने जान-बूझकर भारतीय जमीन चीन को सौंप दी है। राहुल की इस जुमलेबाजी पर मुझे खास आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आस-पास बैठे किसी आदमी ने जैसी चाबी भरी, गुड्डे ने वैसा नाच दिखा दिया। हां, यह तो मानना पड़ेगा कि 'नरेन्दर' को 'सरेन्डर' कहकर तुकबंदी में राहुल ने मोदी को मात कर दिया है। बेहतर होता कि हमारे नेता सार्वजनिक रुप से इस तरह के बयान देने की बजाय इस राष्ट्रीय दुख और अपमान की घड़ी में घर में बैठकर समयानुकूल सलाह-मश्विरा करते और आगे की रणनीति बनाते। यदि मोदी भी चाहते तो जवाहरलाल नेहरु की तरह अकड़ दिखा सकते थे। जैसे नेहरु ने 1962 में श्रीलंका-यात्रा पर जाते हुए कहा था कि मैंने भारतीय फौजों को आदेश दे दिया है कि चीनियों को अपनी सीमा में से मार भगाएं। ऐसा आदेश वर्तमान सरकार दे देती तो उसके परिणाम क्या होते ?

वैसा आदेश जारी करने की बजाय मोदी ने सारी कूटनीति का बोझ अपने ही कंधों पर डाल लिया है। उन्होंने कह दिया कि भारत की सीमा में कोई घुसा ही नहीं। भारत की जमीन पर किसी का भी कब्जा नहीं हुआ है। यदि ऐसा ही है तो यह सारा बवाल हुआ ही क्यों है ? इस संबंध में 16 जून से ही मैं कई सवाल कर चुका हूं। उन्हें अब दोहराने की जरुरत नहीं है लेकिन उन सवालों में से एक का जवाब तो रक्षामंत्री राजनाथसिंह ने दे दिया है। उन्होंने फौज से कहा है कि अब वह सीमांत पर देख-रेख और बातचीत के लिए जाए तो निहत्थे न जाए। हथियारबंद होकर जाए। चीनियों को भी समझ में आ गया होगा कि अब वे 15 जून की रात दुबारा दोहरा नहीं पाएंगे लेकिन मोदीजी का क्या होगा ? वे तो नेहरुजी से भी ज्यादा फंस गए। नेहरु ने 1962 में इतनी हिम्मत तो दिखाई कि चीनियों को निकाल बाहर करने का आदेश उन्होंने दे दिया था, यहां तो बात करने की भी हिम्मत का अभाव है। चीन के सरकारी अखबारों और विदेश नीति विशेषज्ञों ने गलवान-कांड पर मोदी की नरमी और संयम की तारीफकी है। अब भी मौका है कि मोदी पहल करके इस अत्यंत दुखद कांड से आगे बढ़ें। अपनी दुविधा को खत्म करें। या तो जवाबी हमला करें या शी चिन फिंग से बात करें! मामले को सुलझाएं वरना जो जनता आज चीन के खिलाफउठ खड़ी हुई है, वह कल मोदी के खिलाफउठ खड़ी हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इस समय जिस परेशानी को महसूस कर रहे हैं, क्या मोदी को उसका अंदाज है?

चीन से संभव है आर्थिक मुकाबला

डॉ. जयंतीलाल भंडारी
विख्यात अर्थशास्त्री

हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के द्वारा किए गए विश्वासघात और भारतीय जवानों की शहादत के बाद देश के कोने-कोने में चीन विरोधी माहौल दिखाई दे रहा है और लोग चीनी वस्तुओं को जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां देश में चल रही चीन की कई परियोजनाओं को रद्द किया जा रहा है, वहीं सरकारी विभागों के द्वारा चीनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि देश के करोड़ों लोगों के साथ-साथ केंद्र एवं राज्य सरकारें चीन को आर्थिक मोर्चे पर जोरदार टक्कर देने के लिए आगे बढ़ी हैं, उससे चीन पर आर्थिक दबाव दिखाई देना शुरू हो गया है। गौरतलब है कि अक्तूबर 2016 में भारत के द्वारा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चीन के द्वारा पाकिस्तान का साथ दिए जाने के कारण देश के कोने-कोने में भारतीय उपभोक्ताओं के द्वारा चीनी माल का बहिष्कार किया गया था।

इसी तरह जुलाई 2017 में सिक्किम के डोकलाम में चीनी सेना के सामने भारतीय सेना को खड़े कर दिए जाने पर जब चीन ने युद्ध की धमकी दी थी तो भारत में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का जोरदार परिदृश्य दिखाई दिया था। इन दोनों घटनाक्रमों के बाद भारतीय बाजारों में चीनी उपभोक्ता सामान की बिक्री में करीब 25 फीसदी की कमी आई थी। साथ ही चीन से बढ़ते हुए आयात की दर में भी कमी आई थी। वस्तुतः इस समय दिखाई दे रही चीन की बौखलाहट के पीछे कुछ स्पष्ट आर्थिक कारण भी दिखाई दे रहे हैं। चीन से निवेश निकलकर भारत आने का परिदृश्य चीन की बौखलाहट का बड़ा कारण है। प्रख्यात वैश्विक कंपनी ब्लूमबर्ग के द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्ट मई 2020 के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण चीन के प्रति नाराजगी से चीन में कार्यरत कई वैश्विक निर्यातक कंपनियां अपने मैन्युफेक्चरिंग का काम पूरी तरह या आंशिक रूप से चीन से बाहर स्थानांतरित करने की तैयारी कर रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से बाहर निकलती कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत इन्हें बिना किसी परेशानी के जमीन मुहैया कराने पर काम कर रहा है। खास तौर से जापान, अमरीका, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन की कई कंपनियां भारत को प्राथमिकता देते हुए दिखाई दे रही हैं। ये चारों देश भारत के टॉप-10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में शामिल हैं। यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट है। चीन से निर्यात घट गए हैं। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में बड़े देश व्यापारिक हित के कारण भारत के साथ साझेदारी बढ़ा रहे हैं। इन सब कारणों के साथ-साथ अमरीका ने भारत को जी-7 में शामिल होने के लिए खुला निमंत्रण दिया है। ऐसे में जब पूरा देश चीनी सामानों के बहिष्कार की नीति की डगर पर आगे बढ़ गया है, तब निश्चित रूप से चीन से आयात और व्यापार घाटे में कमी आएगी। गौरतलब है कि हाल ही में चीन के सीमा शुल्क सामान्य विभाग (जीएसीसी) के द्वारा भारत-चीन व्यापार संबंधी दी गई जानकारी में कहा गया है कि वर्ष 2001 में दोनों देशों के बीच कारोबार महज तीन अरब डालर का था, फिर वह वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ता गया। भारत और चीन के बीच वर्ष 2018 में द्विपक्षीय व्यापार 95.7 अरब डालर मूल्य का था, वह 2019 में घटकर 92.68 अरब डालर मूल्य का रहा। स्पष्ट है कि वर्ष 2019 में भारत-चीन के बीच व्यापार वर्ष 2018 की तुलना में करीब तीन अरब डालर कम रहा। जहां वर्ष 2018 में चीन ने भारत को 76.87 अरब डालर मूल्य का निर्यात किया, वहीं 2019 में चीन ने भारत को 74.72 अरब डालर मूल्य का निर्यात किया। यानी चीन से भारत को किए जाने वाले निर्यात में भी कमी आई। इसी तरह जहां 2018 में चीन को भारत ने 18.83 अरब डालर मूल्य के निर्यात किए, वही चीन को भारत ने वर्ष 2019 में 17.95 अरब डालर मूल्य के निर्यात किए। दोनों देशों के बीच व्यापार में गिरावट के साथ-साथ वर्ष 2019 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 56.77 अरब डालर रहा।

यह व्यापार घाटा 2018 में 58.04 अरब डालर था। स्पष्ट है कि चीन के साथ व्यापार घाटे में भी कमी आई है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहां हम चीन को एक रुपए मूल्य का निर्यात कर रहे हैं, उसकी तुलना में चीन से करीब साढ़े चार रुपए मूल्य का आयात करते हैं। इतना ही नहीं, चिंताजनक यह भी है कि हमारे कुल विदेश व्यापार घाटे का करीब एक-तिहाई व्यापार घाटा चीन से संबंधित है। यद्यपि भारत विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के तहत चीन के आयात पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। लेकिन भारत सरकार चीनी सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जरूर लगा सकती है। यह एक प्रकार का शुल्क है जिससे चीनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और भारतीय उत्पादक उनका मुकाबला कर सकेंगे। भारत ने चीन से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि उनकी गुणवत्ता अस्वीकार्य थी। इसी तरह कुछ मोबाइल फोन जिन पर अंतरराष्ट्रीय मोबाइल स्टेशन उपकरण पहचान संख्या या अन्य सुरक्षा सुविधाएं नहीं थीं, उन्हें भी प्रतिबंधित किया हुआ है। इसके साथ चीन से कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के मामले में विभिन्न चुनौतियों को देखते हैं तो पाते हैं कि कई वस्तुओं का उत्पादन बहुत कुछ आयातित कच्चे माल और आयातित वस्तुओं पर आधारित है। खास तौर से दवाई उद्योग, मोबाइल उद्योग, चिकित्सा उपकरण उद्योग, वाहन उद्योग तथा इलेक्ट्रिक जैसे कई उद्योग। बहुत कुछ आयातित माल पर आधारित है।

इस समय मैन्युफेक्चरिंग इकाइयों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल चीन से आयात किया जाता है। इस समय जिस तरह चीन के सामानों पर भारत की निर्भरता है, उसके मद्देनजर चीनी सामानों के लिए एकदम कोई विकल्प नहीं तैयार हो सकता है, लेकिन देश में आयात की जा रही वस्तुओं के लिए यदि शीघ्रतापूर्वक हम स्थानीय उत्पादों को तैयार करें और इससे यदि शुरू में हम 50 फीसदी जरूरत भी पूरी कर लें तो यह देश की उपलब्धि होगी। इसके साथ-साथ यह रणनीति भी होनी चाहिए कि अधिक जरूरी आयात के लिए चीन की जगह विकल्प देश का चयन करें। ऐसे में सिंगापुर, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से आयात बढ़ाकर चीन पर निर्भरता कम की जा सकती है। हम उम्मीद करें कि लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के द्वारा किए गए खूनी संघर्ष और भारतीय जवानों की शहादत के बाद अब देश के करोड़ों लोग संकल्प के साथ चीनी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। हम उम्मीद करें कि सरकार के द्वारा चीन से एक ओर कम जरूरी आयातों को नियंत्रित किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर देश के मैन्युफेक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए चीन से आयात की जा रही ज्यादा जरूरी वस्तुओं और कच्चे माल को देश में ही उत्पादित किए जाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी रणनीति से जहां निश्चित रूप से चीन से आयात और व्यापार घाटे में कमी आ पाएगी, वहीं इससे चीन पर आर्थिक दबाव भी बनाया जा सकेगा और चीन से आर्थिक मुकाबला किया जा सकेगा।

छिछोरों के बीच छिछोरापन

अजय पाराशर, लेखक

भले ही ओशो लाख कहते रहें कि हमें जो शरीर मिला है हमें उसके प्रति सदैव कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन हमें न.खुद से प्रेम है और न ईश्वर से। दुनिया को छिछोरा बनाने के बाद उसे अपने छिछोरेपन से जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन सामूहिक छिछोरेपन के आगे वैयक्तिक छिछोरापन बौना हो जाता है। ताउम्र स्वांग रचते हैं और अंततः मसखरे बन निकल पड़ते हैं। जिस तरह राजनेता ढोंग करते हैं जनता और देश से प्रेम और कृतज्ञता काय वैसे ही हम दिखावा करते हैं खुद से और खुदा से प्यार और आभार का। भैंस की तरह जुगाली करते हुए न जाने किस दुनिया में खोए हुए व.क्त गुजारते हैं। जब तक दुनिया में हैं हमारा व्यवहार ऐसा होता है मानो सांसें उधार की हों। कहते हैं आदमी का व्यवहार आज से नहीं सृष्टि के आरंभ से ही ऐसा है। बस परिस्थितियों के हिसाब से गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अगर शक्ति या सत्ता नहीं होगी तो दीन-हीन बना रहेगा और जैसे ही सत्ता मिली, वैसे ही रंग बदल कर दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आधुनिक कहावत क्यों गढ़ी जाती, 'छिछोरे तेरे कितने नाम, परसू, परसा, परस राम।' प्रकृति सामूहिक मन पर कितना असर डालती हैय इसका एहसास हमें तभी हो सकता है जब हम संवेदनशील हों। लेकिन जब मन पर गैंडे की खाल की तरह छिछोरेपन की परत पड़ी हो तब चाहे कोरोना संक्रमण हो या दुश्मन से युद्ध जैसे हालातय हमें केवल छिछोरापन ही सूझता है। नहीं तो विश्व के सबसे दबंग देश में गोरी टांग आज भी काली गरदन पर हावी क्यों होती? भक्त खुंदक में 'दुश्मन के पहरुए' का तमगा किसी और के गले क्यों टांगते? बिना सोचे-समझे स्वघोषित पहरुआ क्यों बोलता कि चोर तो हमारे खेत में आया ही नहीं था। 'छिछोरे' फ़िल्म का चीफछिछोरा अपनी .कुव्वत और छिछोरेपन से अपने फिसड्डी हॉस्टल को ऊंचाई पर ले जाने और.खुदकुशी की कोशिश करने वाले बेटे को वापस जिंदगी की पटरी पर लाने के बावजूद असल जिंदगी में खुदकुशी क्यों करता? सा.फहै कि हम वहीं तक देखते हैं जहां तक नजर जाती है। लेकिन जो नजरों के पार देख सकता है वह कभी हार नहीं मानता। सुख-दुःख तो रात-दिन की तरह जिंदगी में आते-जाते रहते हैं। गिनती के ऐसे ही चंद लोगों से दुनिया चलती है। नाम 'सुशांत' होने से कोई श.ख्स सचमुच सुशांत तो नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तो अमीर चंद हमेशा अमीर ही पैदा होता। नाम तो गहनों की तरह गढ़े जाते हैं। कभी मां-बाप उत्साह में बच्चों के नाम रखते हैं तो कभी राजनीति के लिए नाम रखे या बदले जाते हैं। लेकिन छिछोरेपन में जीतता वही है जो जाती तौर पर भी अव्वल दरजे का छिछोरा होने के साथ छिछोरेपन को सामूहिकता में जीने का हुनर जानता हो। अगर ऐसा नहीं होता तो बॉलीवुड के असली छिछोरे 'सुशांत' जैसे फ़िल्मी छिछोरे को खुदकुशी करने पर मजबूर करने की बजाय खुद आत्महत्या कर लेते। इससे साबित होता है कि छिछोरेपन में न्यूटन का तीसरा नियम पूरी तरह लागू नहीं होता। छिछोरेपन में हर क्रिया की प्रतिक्रिया तभी मुमकिन है, जब दूसरा छिछोरा पहले छिछोरे से ज्यादा बड़ा छिछोरा हो। भले ही वैयक्तिक छिछोरापन व.क्त के सामने हार जाए लेकिन सामूहिक छिछोरेपन के आगे व.क्त भी हार जाता है। छिछोरापन सदियों से अमरबेल की तरह फल-फूल रहा है।

कोरोना ने विवाहों की आलीशान रश्में सीमित की

कोरोना वैश्विक महामारी के प्रकोप से सारी दुनिया जूझ रही है। भारत में इस बीमारी से लड़ने सबसे पहले 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर देश व्यापी जनता कर्फ्यू लगाया गया। दिनांक 24 मार्च से देश व्यापी लाँकडाउन लगाया।

इस बीमारी से बचने दुनिया में आज तक कोई दवा नहीं बनी है। देश में कोरोना वायरस समुदाय को अपना शिकार न बनाये, इसके लिये मास्क लगाना, सामाजिक दूरी रखना और बार बार हाथ धोने की अपील की जा रही है। भारत की जनसंख्या एक अरब तीस करोड़ है। लाँकडाउन एवं सरकार के प्रयासों से अभी तक मात्र लगभग 4 लाख लोग कोरोना संक्रमित हुए है, जिनमें आधे से अधिक ठीक हो गये हैं। आज भी देश में कोरोना की भयावह स्थिति से सब अपने आपको सुरक्षित रखने चिन्तित हैं।

हम आज चर्चा कर रहे है विवाह समारोह के नाम पर होने वाले वैभव प्रदर्शन एवं पैसे की बर्बादी की। जब से देश में कोरोना की रोक थाम के लिये लाँकडाउन लगा। विवाह समारोह शासकीय प्रतिबंधों के साथ सम्पन्न कराने के आदेश जारी हुए, आलीशान और वैभव से लवरेज विवाह समारोहों पर ग्रहण लग गया। भारतीय प्राचीन संस्कृति में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक सोलह संस्कारों का उल्लेख है। इन सोलह संस्कारों में एक विवाह संस्कार या पाणिग्रहण संस्कार होता है। व्यक्ति के जीवन का यह प्रमुख संस्कार माना गया है। युवक एवं युवती धार्मिक विधि विधान से सात फेरे लेकर पति पत्नी के रूप में गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं। विवाह संस्कार पंडितजी द्वारा दोनों पक्षों के परिजनों के समक्ष सम्पन्न कराया जाता है। परिवार एवं समाज जन इस विवाह के साक्षी होते हैं।

पिछले लगभग 25-30 वर्षों से विवाह समारोहों में निरंतर वैभव प्रदर्शन, धन की बर्बादी एवं अश्लीलता का बोल बाला बढ़ता जा रहा है। विवाह समारोह आलीशान मेरिज गार्डन में होने लगे। आशीर्वाद समारोह में तीन से चार हजार आमंत्रण पत्र दिये जाते है। आशीर्वाद समारोह रात्री 8 बजे प्रारंभ होता है जो देर रात 12 तक चलता है। स्वरुचि भोजन में लगभग 70 से 100 तक व्यंजन बनाये जाते है। बैंड, मेहमानों को ठहराने होटल, टैक्सियों को किराये पर लिया जाता है।

मेहमानों को विवाह के उपलक्ष में कीमती गिफ्ट दी जाती हैं। जिस समय बारात निकलती है उस समय सड़क पर सभ्रांत परिवारों की महिलाएं फूहड़ नृत्य करके मर्यादाओं को तार तार करती हैं।

इन वैवाहिक रश्मों में एक और कुप्रथा ने जन्म लिया है, उसे विवाह पूर्व फिल्मांकन या चतम ूमककपदह ेिववज कहते हैं। विवाह से पूर्व युवक युवती किसी हिल स्टेशन या पर्यटन स्थल जाते हैं वह कुछ रूक कर विभिन्न क्रिया कलापों का फिल्मांकन कराते हैं। उस विवाह पूर्व फिल्मांकन को आशीर्वाद समारोह में बड़े पर्दे पर लगातार दिखाया जाता है।

सुप्रसिद्ध जैन मुनि सुधासागर जी सहित अनेक संतों ने जैन समाज को आव्हान किया कि विवाह समारोह दिन में सम्पन्न करें। आशीर्वाद समारोह में सीमित व्यंजन बनाये जाये।

बारात में महिलाओं का नृत्य बंद किया जाये एवं रात्री में होने बाले महिला संगीत को बंद किया जाये। संतो के आदेश का जैन समाज ने अनेक नगरों में अनुशरण किया। मगर देश में विवाह समारोहों के नाम लाखों करोड़ों रुपये की बर्बादी नहीं रोक पाये। भारत में जैसे ही 24 मार्च से लाँकडाउन लगा, लाँकडाउन में विवाह समारोहों को ही प्रतिबंधित कर दिया था। लाँकडाउन खुलने के बाद विवाह समारोह पूर्ण सादगी पूर्ण सम्पन्न हो रहे है। मेरीज गार्डन, बैंड बाजे, आशीर्वाद समारोह,

विजय कुमार जैन

बारात निकालने की अनुमति नहीं हैं। पिछले तीन माह जहाँ हजारों विवाह वैभव प्रदर्शन के साथ होते वह नहीं हो सके। शासन की अनुमति जो विवाह गत दिनों सम्पन्न हुए हैं, उनमें दोनों पक्षों के मात्र 50 लोगों को सम्मिलित होने की ही अनुमति दी जाती है। पिछले तीन माह में प्रतिबंधों के चलते देश में करोड़ों नहीं अरबों रुपये कि बर्बादी रुकी है। जिस कुप्रथा या वैवाहिक फिजूल खर्ची रुकबाने संत और समाज सुधारक निरंतर प्रयास करते रहे वह नहीं रुकपायी। इस पर आंशिक रोक कोराना महामारी की रोकथाम के नाम पर लग गई। हमे यह देखना हैं विवाह के नाम पर वैभव प्रदर्शन पर कब तक प्रतिबंध रहता है।

बाल मजदूरी बढ़ने का खतरा

संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच लाखों बच्चों पर कम उम्र में मजदूरी का खतरा मंडरा रहा है। इस पर गौर करने की जरूरत है, वरना इस कलंक को मिटाने की कई दशकों से की गई कोशिश पर पानी फिर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2000 के बाद यह पहला मौका हो सकता है, जब बाल श्रम के संकट में फिर से बढ़ोतरी दर्ज हो। कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट सही वक्त पर आई है। अभी हकीकत यह है कि महामारी के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था डांवाडोल हो चुकी है, जिस कारण लाखों लोग गरीबी में गिरते जा रहे हैं। ऐसे परिवारों में अपने बच्चों को काम पर भेजने की प्रवृत्ति सहज रूप से बढ़ सकती है। ये हकीकत है कि इस वक्त दुनिया में सिर्फकोरोना वायरस महामारी की चर्चा है। उसमें पहले से मौजूद या महामारी के कारण खड़ी हो रहीं दूसरी समस्याओं पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनमें बाल श्रम का मुद्दा भी है। भारत में बाल श्रम के खिलाफकानून तो है, फिर भी बाल मजदूरी धड़ल्ले से होती है। मानव तस्कर हो या फिर आपराधिक गुट बच्चों को बाल श्रम में धकेल रहे हैं। ईंट भट्ठों, निर्माण कार्यों आदि जैसी जगहों पर बच्चों से काम लिया जाता है।

जाहिर है, सरकारी और सामाजिक स्तर पर बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाने के तमाम प्रयासों के बावजूद इस पर अब तक अंकुश नहीं लग पाया है। अब कोरोना महामारी से बन रहे हालात में इसमें नया आयाम जुड़ गया है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के मुताबिक दुनियाभर में बाल श्रमिकों की संख्या साल 2000 में 24 करोड़ 60 लाख थी, जो घट कर सवा 15 करोड़ तक आ गई थी। लेकिन कोरोना महामारी से वो हालत पलट दिए हैं, जिनकी वजह से ये प्रगति हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफके मुताबिक जैसे-जैसे गरीबी बढ़ेगी, स्कूल बंद होंगे और सामाजिक सेवाएं कम होती जाएंगी और अधिक संख्या में बच्चों को बाल श्रम में धकेल दिया जाएगा। भारतीय श्रम कानून के मुताबिक 15 साल से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना गैर कानूनी है। लेकिन स्कूल के बाद वे परिवार के व्यवसाय में हाथ बंटा सकते हैं। इस प्रावधान का पहले ही दुरुपयोग किया जाता रहा है, जिसकी वह से बड़ी संख्या में बाल मजदूर मौजूद रहे हैं। अतः भारत में सरकारों को अधिक सतर्क हो जाने की जरूरत है।

विराट का छोटा-सा अनुभव सब कुछ बदल देता है

रवींद्रनाथ ने लिखा है कि जब उनकी गीतांजलि प्रकाशित हुई और उन्हें नोबल प्राइज मिला। नोबल प्राइज जब तक न मिला था, तब तक तो कोई फिक्र उनकी करता नहीं था। जब नोबल प्राइज मिला, तो स्वागतसमारंभ शुरू हो गए। सारे कलकत्ते ने स्वागत किया। विरोधी भी मित्र बन गए।

लेकिन एक बूढा उनके पडोस में था, जो नोबल प्राइज से जरा भी न डरा। और वह उन्हें बडा परेशान किए हुए था, कि जब उनकी कविताएं छपती थीं, तो वह अक्सर उनको रास्ते में मिल जाता आते-जाते और कहता कि सुन! परमात्मा का अनुभव हुआ है? क्योंकि वे परमात्मा के बाबत कविताएं लिख रहे थे। ऐसा उनसे कोई भी नहीं पूछता था। कविता ठीक है कि नहीं, यह अलग बात है। लेकिन ऐसा उनसे कोई भी नहीं पूछता था कि परमात्मा का अनुभव हुआ है! ऐसी तेज आंख से देखता था कि रवींद्रनाथ ने कहा है कि उस आदमी से जितना मैं डरता था, किसी से भी नहीं डरता था। और हिम्मत भी नहीं पडती थी कहने की कि अनुभव हुआ है, क्योंकि अनुभव हुआ भी नहीं था। और उससे कहने में कोई सार भी नहीं था। उसकी आंख ही डरा देती थी।

रवींद्रनाथ ने लिखा है कि मैंने बडे प्रेम के गीत गाए, बडी मित्रता के, लेकिन मेरे मन में उस बूढे के प्रति कोई सद्भाव कभी नहीं जन्मा। मैं सारे जगत के प्रति प्रेम का गीत गा सकता था उस बूढे को छोडकरय वह जो का था, वह जो पडोस में ही रहता था! और उसका जो व्यवहार था, वह ऐसा था कि बडा कठोर था।

फिर रवींद्रनाथ ने लिखा है कि लेकिन एक दिन सारी बात बदल गई। जा रहा था समुद्र के किनारे, वर्षा हुई थी थोडी, और रास्ते के किनारे डबरों में पानी भर गया था। सांझ उतर गई। चांद आ गया। पूरे चांद की रात थी, डबरों में, गंदे डबरों में सडक के किनारे, चांद की छवि बनने लगी, बडी प्यारी। फिर सागर के किनारे जाकर देखा चांद को। फिर अचानक एक खयाल आया कि चांद तो चांद ही है, चाहे सागर का स्वच्छ जल हो और चाहे सडक के किनारे बने गंदे डबरे का गंदा जल हो, चांद के प्रतिबिम्ब में तो कोई गंदगी नहीं होती। चाहे वह गंदे डबरे में बन रहा हो और चाहे स्वच्छ जल में बन रहा हो, प्रतिबिम्ब तो गंदा नहीं होता गंदे जल के कारण।

इस खयाल के आते ही समाधि लग गई। यह खयाल अनूठा है। इसका मतलब हुआ कि सीमाएं सब टूट गईं और प्रतिबिम्ब कहीं भी बन रहा हो उसका, चाहे राम में, चाहे रावण में, बराबर हो गया। समाधि लग गई, आनंद से ह्रदय भर गया। नाचता हुआ घर की तरफलौटने लगा। रास्ते पर वह आदमी मिला। आज मुझे डरा नहीं पाया, आज उसे देखकर भी मैं आनंदित हुआ। उसे मैंने गले लगा लिया। आज उसने मेरी आंख में आंख झांककर देखा, लेकिन मुझसे कहा नहीं कि क्या ईश्वर का अनुभव हुआ है। उसने कहा, तो अच्छा, हो गया! मालूम पडता है, हो गया।

रवींद्रनाथ ने लिखा है, उस दिन के बाद तीन दिन तक ऐसी दशा बनी रही कि जो मिल जाए, उससे ही गले मिलने का हो मनमित्र हो कि शत्रु हो, अपरिचित कि परिचित, नौकर, मित्र कोई भी हो। और फिर आदमी चुक गए, तो गाय, घोडे, उनसे भी गले मिलना होने लगा। फिर वे भी चुक गए, तो वृक्ष, पत्थर, दीवार और रवींद्रनाथ ने लिखा है कि दीवार से मिलकर भी वही अनुभव होने लगा, जो अपनी प्रेयसी से मिलकर हो।

लेकिन उस दिन लगा कि अब तक जो मैंने लोगों से व्यवहार किया है, वह बडा बुरा था। जाकर क्षमा मांगने गया उस बूढे से कि मुझे माफकर दो। मैं तुम्हें पहचान ही न पाया कि तुम कौन हो। आज पहचान पाया हूं तो सबसे क्षमा मांगने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है।

जिस दिन आपको भी थोडी-सी झलक मिलेगी, सिवाय क्षमा मांगने के और कोई उपाय नहीं रह जाएगा। क्योंकि चारों तरफवही विराट मौजूद है, और हम उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वह बडा ओछा है। पर होगा ही व्यवहार ओछा, क्योंकि दृष्टि ओछी है. क्योंकि वह विराट तो कहीं दिखता ही नहीं है।

धारा 370 को समाप्त करने के पक्ष में थे डॉ. मुखर्जी

पुण्यतिथियां तो अनेकों महापुरूषो की मनायी जाती है और आगे भी मनायी जाती रहेगी। वे पुण्यात्मा बहुत भाग्यशाली होते हैं, जिनके समर्थक या विचारधारा पर चलने वाले उनके 'बलिदान' को अपने प्रयासों से उसे सार्थक कर दुनिया के सामने इतिहास रचते हैं। 23 जून को डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। यह पुण्यतिथि असामान्य और असाधारण कहा जाएगा। अखण्ड भारत के लिए डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि भारत में यानि एक देश में 'दो निशान, दो विधान एवं दो प्रधान' नहीं चलेंगे। उन्होने भारतीय संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को कहा था कि 'या तो मैं संविधान की रक्षा करूंगा नही तो अपने प्राण दे दूंगा'। हुआ भी यही। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी परमिट बिना जम्मू-कश्मीर गए। उन्हे शेख अब्दुल्ला की सरकार ने गिरफ्तार किया। उन्होने कहा मैं इस देश का सांसद हूँ। मुझे अपने देश में ही कहीं जाने से आप कैसे रोक सकते हैं। उन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद उन्हें मृत घोषित किया गया। वे अखंड भारत के लिए बलिदान देने वाले पहले भारतीय थे, जो जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में वहां गए थे।

23 जून के उसी बलिदान दिवस को भारतीय जनसंघ और अब भाजपा पुण्यतिथि के रूप में मनाती है। भारतीय जनसंघ से लेकर भाजपा के प्रत्येक घोषणा पत्र में अपने बलिदानी नेता डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के इस घोष वाक्य को, कि 'हम संविधान की अस्थायी धारा 370 को समाप्त करेंगे', सदैव लिखा जाता रहा। समय आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो स्वयं डॉ. मुरली मनोहर जोशी के साथ भारत की यात्रा करते हुए श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, और गृहमंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को राष्ट्रहित में समाप्त करने के निर्णय को दोनों सदनों से पारित कर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा मां भारती के लिए जीवन देनें को सच्ची श्रद्धांजली दी। वे महापुरूष बहुत भाग्यशाली होते हैं, जिनकी आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों के मां भारती के लिए कही गई बातों को साकार करते हैं। सच में डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी भाग्यशाली हैं कि उनके विचार के संवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह सहित पूरे मंत्रीमंडल ने धारा 370 को समाप्त कर दुनिया को बता दिया।

'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है,

जो कश्मीर हमारा है, वह सारा का सारा है।'

राष्ट्रभक्ति की आंचल में राष्ट्रपुरुष का निर्माण

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और राष्ट्रभक्त माता-पिता की संतान थे जिनकी प्रसिद्धि न केवल बंगाल बल्कि सम्पूर्ण भारत में थी। धर्म एवं संस्कृति के प्रति आदर तथा राष्ट्रीयता की प्रेरणा उन्हें अपने माता-पिता से मिली थी। अपनी मां योगमाया देवी से धार्मिक एवं ऐतिहासिक कथाएं सुन-सुनकर जहां देश और संस्कृति की जानकारी प्राप्त की, वहीं अपने पिता आशुतोष मुखर्जी के साथ बैठकर राष्ट्रभक्ति की शिक्षा को आत्मसात किया।

आत्मबोध की दिशा में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिक्षा, राजनीति, समाज-संस्कृति सभी क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1929 में बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने, 1934 से 1938 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के उप-कुलपति रहे, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए, बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री रहे, महाबोधि सोसाइटी एवं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष रहे, संविधान सभा के सदस्य बने, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बने, 1952 के पहले आम चुनाव में दक्षिण कलकत्ता संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद भी बने। लेकिन राष्ट्रपुरुष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प था कि भारत एक मजबूत एकीकृत राष्ट्र बने और इस अभियान को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आप तनिक चिंतन करें, पहले भारत के नेता कैसे होते थे उसका अनुपम उदाहरण भारतीय राजनीति में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हैं।

मां भारती के सच्चे सपूत ने विभाजन का विरोध किया

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत का विभाजन नहीं होने देना चाहते थे। इसके लिए वे महात्मा गांधी के पास भी गये थे। परंतु गांधीजी का कहना था कि कांग्रेस के लोग उनकी बात सुनते ही नहीं। जवाहर लाल नेहरू भी विभाजन के पक्ष में थे। जब देश का विभाजन अनिवार्य जैसा हो गया, डॉ. मुखर्जी ने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिंदुओं के हितों की उपेक्षा न हो। उन्होंने बंगाल के विभाजन के लिए जोरदार प्रयास किया, जिससे मुस्लिम लीग का पूरा प्रांत हड़पने का मंसूबा सफल नहीं हो सका। उनके प्रयत्नों से हिंदुओं के हितों की रक्षा तो हुई ही कलकत्ता बंदरगाह भी पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) को सौंपे जाने से बच गया। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आ रहे हिंदुओं की दुर्दशा से वे विचलित थे। उन्होंने विस्थापितों के बीच रहकर उनको लाभान्वित करने वाली योजनाओं की पहल की।

नेहरू द्वारा विस्थापितों के प्रति उपेक्षा और राष्ट्र हितों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने अंततः 8 अप्रैल 1950 को नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, जिसमें वे 1947 में गांधीजी के निमंत्रण पर शामिल हुए थे। डॉ. मुखर्जी ने अनुभव किया कि नेहरू पाकिस्तान सरकार के प्रति बहुत ज्यादा नरम रवैया रखे हुए हैं और उनमें पश्चिमी (वर्तमान पाकिस्तान) और पूर्वी पाकिस्तान(वर्तमान बांग्लादेश) में छूट गए हिंदुओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने का कोई साहस नहीं है। उनका स्पष्ट मानना था कि नेहरू-लियाकत समझौता निर्थक था क्योंकि इसमें भारत सरकार पर तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी डाली गई थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसे ही आचरण की कोई पहल नहीं की गई थी। त्यागपत्र देने के बाद डॉ. मुखर्जी ने संसद में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से वे प्रतिपक्ष राजनीतिक मंच के गठन की संभावनाओं को तलाशने की ओर अग्रसर हुए। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ का गठन हुआ जिसके वे संस्थापक अध्यक्ष बने। डॉ. मुखर्जी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था 'आज भारतीय जनसंघ के रूप में एक नए अखिल भारतीय राजनीतिक दल का उदय हो रहा है जो देश का प्रमुख प्रतिपक्षी दल होगा। यद्यपि भारत अद्वितीय विविधताओं का देश है, तो भी इस बात की परम् आवश्यकता है कि मातृभूमि के प्रति गहरी भक्ति भावना और निष्ठा की चेतना में से विकसित होने वाला बंधुत्व भाव और विवेक समस्त देशवासियों को एक सूत्र में बांधे।' हम सभी को ज्ञात है कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परमपूज्य माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरूजी) से भेंट की और उनसे आग्रह कर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। गुरूजी ने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को उसी समय अपने आठ प्रचारकों को भारतीय जनसंघ का कार्य प्रारंभ करने के लिए मुक्त किया था। यही से जनसंघ का कार्य प्रारंभ हुआ।

आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटालिटी

देश में पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ। भारतीय जनसंघ को तीन सीटें मिली। डॉ. मुखर्जी भी दक्षिण कलकत्ता संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत कर लोकसभा में आए। यद्यपि उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं था लेकिन वे संसद में डेमोक्रेटिक एलायन्स के नेता थे। सदन में नेहरू की नीतियों पर तीखा प्रहार करते थे। सदन में बहस के दौरान नेहरू ने एक बार डॉ. मुखर्जी की तरफ इशारा करते हुए कहा था 'जनसंघ एक कम्यूनल पार्टी है, आई विल क्रश जनसंघ।' इस पर डॉ. मुखर्जी ने जवाब देते हुए कहा, 'माय फ्रेंड पंडित जवाहर लाल नेहरू सेज देट ही विल क्रश जनसंघ, आई से आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटालिटी।' संसद में संख्या की दृष्टि से थोड़े होते हुए उनका इतना प्रभाव था कि चाहे कश्मीर पर चर्चा हो या कोई और विषय हो, उनके भाषण को सब पूरे ध्यान से सुनते थे। उनके इस दृढ़ता और समर्पण का ही परिणाम है कि आज देश में उन सिद्धांतों पर चलने वाली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की बहुमत वाली सरकार है, जो नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक के इतिहास की गलतियों को ठीक करते हुए राष्ट्रहित और जनहित में फैसले ले रही है।

संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर अपना जीवन बलिदान कर दूंगा

जिस समय संविधान सभा में धारा 370 पर विचार-विमर्श हो रहा था, शेख अब्दुल्ला की बात मानकर जवाहरलाल नेहरू स्वयं विदेश चले गए। यह एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया। नेहरू मंत्रिमंडल में बिना विभाग के मंत्री रहे गोपालस्वामी अयंगर, जो जम्मू-कश्मीर के राजा हरि सिंह के दीवान रहे थे, को नेहरू खासतौर पर जम्मू-कश्मीर के लिए ही कैबिनेट में लाए थे। विदेश जाने से पहले यह जिम्मेदारी नेहरू ने अयंगर को देकर गए थे। धारा 370 का प्रावधान कांग्रेस संसदीय दल के समक्ष आया और वहां भी विरोध हुआ। घबराये अयंगर सरदार पटेल के पास पहुंचे। उन्होंने भी इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन अस्थायी व्यवस्था की गई। सरदार पटेल का कहना था नेहरू होते तो इसे ठीक कर देता लेकिन अभी तो मानना होगा। सरदार पटेल का असामयिक दुनिया से चला जाना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। धारा 370 के कारण कश्मीर की समस्या भले ही बाद में लोगों को दिखाई दी हो, डॉ. मुखर्जी उसकी गंभीरता को आरंभ में ही समझ गए थे। लोकसभा में 1952 के उनके भाषण अगर देखे जाएं तो साफ हो जाएगा कि बाद में कश्मीर में जो कुछ हुआ, आतंकवाद और हिंदुओं के साथ अत्याचार एवं पलायन, उन्होंने तब देख लिया था।

जम्मू-कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की पृथकतावादी राजनीतिक गतिविधियों से उभरी अलगाववादी प्रवृतियां 1952 तक बल पकड़ने लगी थीं। इससे राष्ट्रीय मानस विक्षुब्ध हो उठा था। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रजा परिषद के सत्याग्रह को पूर्ण समर्थन दिया जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना था। समर्थन में उन्होंने जोरदार नारा बुलंद किया था -'एक देश में दो निशान, एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।' अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त करते हुए कहा 'या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा।'

26 जून 1952 को संसद में दिए अपने ऐतिहासिक भाषण में डॉ. मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरासर गलत नीतियों को निर्भयतापूर्वक बेनकाब किया था। उन्होंने कहा था 'क्या जम्मू-कश्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के हकदार नहीं है जिन्हें हमने जम्मू-कश्मीर को छोड़ सारे भारत के लोगों को दिया है? शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का शहंशाह किसने बनाया है? जबकि विलय भारतीय सेनाओं के कश्मीर में प्रवेश करने के कारण ही सम्भव हो सका। क्या यह इसलिए किया गया था कि एक संप्रभु गणतंत्र के अंतर्गत एक और संप्रभु गणतंत्र का निर्माण हो? विभिन्न संगठक इकाईयों के लिए न तो अलग-अलग संविधानों की जरुरत है और न ही इन इकाईयों में भेदभाव जरुरी है।'

अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने नई दिल्ली में नेहरू सरकार और श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला की सरकार को चुनौती देने का निश्चय किया। मई 1953 में जम्मू-कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। उनका उद्देश्य वहां जाकर स्थिति का अध्ययन करना था। उन दिनों जम्मू-कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ता था। लेकिन उन्होंने बिना परमिट जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने संप्रभु गणतंत्र भारत के अंदर दूसरे संप्रभु गणतंत्र के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने कहा था 'विधान लूंगा या अपने प्राण दूंगा।' जब उनसे परमिट मांगा गया तो उन्होंने कहा 'मैं भारत की संसद का सदस्य हूं, मैं अपने ही देश में कश्मीर में परमिट लेकर नहीं जाऊंगा।' उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। 40 दिन तक न उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और न अन्य बुनियादी सुविधाएं दी गई। 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। अपने संकल्प को साकार करने के लिए डॉ. मुखर्जी ने भारत माता के चरणों पर अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया।

प्रभात झा, लेखक

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके साथ कश्मीर गए थे, ने लिखा है 'जब उनकी मृत्यु हो गई तो मुझे लगा कि डॉ. मुखर्जी कह रहे हैं, आसमान से उनकी आत्मा कह रही है कि-लुक आई हेव कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दो एज ए मारटीयर, वो मुझे बंद नहीं रख सके।' अटल जी ने यहीं प्रण किया कि वे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करनें में अपना पूरा जीवन समर्पित करेंगे। यह बलिदान स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला बलिदान था जिसने देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संघर्ष की नींव रखी। कलकत्ता में उनके अंतिम संस्कार में 2 लाख से अधिक लोग श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए। युवा, वृद्ध सभी उनकी अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सड़कों पर उतर आये। डॉ. मुखर्जी का संकल्प राष्ट्र का संकल्प बन गया। उनका बलिदान राष्ट्र के जन-जन के लिए धारा 370 की समाप्ति का प्रण बन गया।

राष्ट्र के इतिहास में विरले ही ऐसे क्षण होते हैं जब एक अद्भुत निर्णय से इतिहास की धारा और राष्ट्र की यात्रा एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से अनुप्राणित हो उठती है। 5 अगस्त 2019 का क्षण वैसा ही था जब जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच विभाजक-रेखा खींचने वाली संविधान की धारा 370 को संसद के दोनों सदनों के एक स्वरीय अनुमोदन से समाप्त कर दिया गया। जो काम पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ, अपने दूसरे कार्यकाल के 70 दिनों के भीतर नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिखाया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने साबित किया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता सर्वोपरि है। राष्ट्रीय एकता के धरातल पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित भारत ने एक सुनहरे भविष्य की नींव रखी है। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जम्मू-कश्मीर की लड़ाई लड़ने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। 'एक विधान, एक निशान और एक प्रधान' का नारा देते हुए 23 जून 1953 को उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। देश में 23 जून को श्एक प्रधान, एक विधान और एक निशानश् दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इससे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को हर वर्ष उनके बलिदान दिवस पर राष्ट्र उन्हें याद तो करेगा ही, देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना बलवती होगी। मां भारती के चरणों पर अपना जीवन अर्पण कर देने वाले इस महानतम और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रभक्त के लिए इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं हो सकती।

न्यूज ब्रीफ

3 मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हुए, 63 की आई नेगेटिव रिपोर्ट

माही की गूंज, खरगोन। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा मंगलवार को हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 3 मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हुए। जबकि पिछले 24 घंटे में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि की गई है। इसके अलावा 63 सैंपलों की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा 95 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए है। अब 290 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। इस तरह जिले में कुल 264 कोरोना से संक्रमित है। इनमें 206 स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हुए। जबकि 14 की मृत्यू तथा 44 मरीज स्थिर है। जिले में कुल 31 कंटेनमेंट एरिया घोषित है।

जिले की 9 तहसीलों में हुई 9.1 औसत वर्षा

माही की गूंज, खरगोन। पिछले 24 घंटे में जिले की 8 तहसीलों में 9.1 औसत वर्षा हुई है। इन तहसीलों में सबसे ज्यादा वर्षा भीकनगांव में हुई। भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भीकनगांव तहसील में 28 मिमी वर्षा हुई है। जबकि खरगोन में 21.6, भगवानुपरा में 14, बड़वाह में 10, झिरन्या में 7, कसरावद में 6 तथा सनावद व महेश्वर में 2-2 मिमी वर्षा हुई है। इसके अलावा गोगांवा व सेगांव में वर्षा नहीं हुई है। जिले में 1 जून से 23 जून तक की स्थिति में कुल 174.7 औसत वर्षा हो चुकी है।

कंटेनमेंट एरिया में काढ़े का किया वितरण

माही की गूंज, खरगोन। आयुष विभाग द्वारा जीवन अमृत योजनांतर्गत मंगलवार को बालाजीपुरम कंटेनमेंट क्षेत्र में त्रिकटू काढ़े का वितरण किया। जिला आयुष अधिकारी डॉ. वासुदेव आसलकर ने बताया कि कलेक्टर गोपालचंद्र डाड से प्राप्त निर्देशों पर यहां निवास करने वाले व्यक्तियों को काढ़ा वितरित किया गया। इस दौरान दल द्वारा 56 परिवारों को त्रिकटू काढ़े का वितरण किया गया। इसके अलावा कसरावद के वार्ड क्र.4 केंटेनमेंट एरिया में मेडिसीन का वितरण किया गया।

खरगोन में मंगलवार को रहा 33.5 डिग्री तापमान

माही की गूंज, खरगोन। खरगोन में मंगलवार को 33.5 डिग्री तापमान रहा, जो सोमवार की तुलना में 1.5 डिग्री कम है। मौसम वैद्यशाला तहसील कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को खरगोन में 33.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री रहा। गत सोमवार 22 जून को खरगोन में 35 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था।

स्कूल शिक्षा की गतिविधियों एवं प्राथमिकताओं पर फेसबुक लाइव 27 जून को

माही की गूंज, खरगोन। कोरोना संकट काल में स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों एवं प्राथमिकताओं पर 27 जून को प्रातः 11 बजे से फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव सत्र का आयोजन किया जाएगा। जिसके माध्यम से शिक्षकों एवं मैदानी सहयोगियों को वरिष्ठ अधिकारी एवं विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त ने सभी संभाग के संयुक्त संचालक, सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देशित किया है कि इस फेसबुक लाइव में शिक्षकों एवं अन्य मैदानी सहयोगियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

सेगवाल तालाब को पट्टे पर देने के प्रस्ताव का हुआ अनुमोदन

जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की हुई बैठक

माही की गूंज, बड़वानी।

जिला पंचायत बड़वानी प्रशासकीय समिति की बैठक, समिति की प्रधान लतादेवी रावत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । इस बैठक के दौरान विगत बैठको के निर्णय का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । वही मत्स्य विभाग द्वारा प्रस्तुत सेगवाल तालाब को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर देने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।

बैठक में समिति की प्रधान लतादेवी रावत, सदस्य रमेश चौहान, राजू मोगरे, कन्हैयालाल सिसोदिया, जवसिंह मुजाल्दे, रंजना पटेल, गीता चौहान, निर्मला श्याम बरडे, जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मगनसिंह कनेश सहित समस्त विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान सहायक संचालक मत्स्य एमके पानखेड़े ने सेगवाल एवं लोअर गोई जल संरचनाओं को अगामी 10 वर्ष के लिये मत्स्य पालन हेतु दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिस पर समिति के सदस्यों ने विचार - विमर्श कर निर्णय किया कि सेगवाल तालाब को पूर्व से कार्यरत जय आदिवासी मछुआ जल कृषि सहकारी समिति को उनके आवेदन के आधार पर पुनः दिया जाये। जबकि समिति के सदस्यों ने निर्णय किया कि कोर्ट में लोअर गोई डेम को लेकर प्रकरण चल रहा है। अतः जब तक कोर्ट का निर्णय नही आ जाता, तब तक इस तालाब को 10 वर्षीय पट्टे पर देने का निर्णय न लिया जाये। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम ने जिले में लौटे प्रवासी श्रमिको के लिये संचालित कार्यो एवं उनके पंजीयन तथा कुशलता मैपिंग के लिये किये जा रहे कार्यो से भी अवगत कराया।

4 हजार से अधिक कार्यों में, 40 हजार से अधिक मजदूरों को रोजगार

माही की गूंज, बड़वानी।

जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम ने बताया कि लॉक डाउन के कारण जिले में लौटे प्रवासी मजदूरो को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये वर्तमान में प्रतिदिन 4 हजार 510 कार्यो का संचालन कर 41 हजार 465 लोगो को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं बड़ी संख्या में और कार्यो का मस्टर जारी करवाकर रखा गया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर संबंधित जनपद पंचायत सीईओ तत्काल इन कार्यो को प्रारंभ करवा सके ।

सरियाम ने बताया कि बड़वानी जिले की 416 ग्राम पंचायतो में से 412 ग्राम पंचायतो में संचालित इन 4 हजार 510 कार्यो में 320 कपीलधारा, 3059 आवास, 12 सुदूर सम्पर्क सड़क, 32 सीसी रोड़, 190 खेत तालाब, 44 पौधारोपण, 12 आंगनवाड़ी, 2 राजीव गांधी सेवा केन्द्र, 8 निस्तार तालाब, 3 तालाब जीर्णोद्वार, 24 चेक डेम, 65 बोल्डर चेक डेम,, 192 सीपीटीसीसीटी, 6 नाडेब वर्मी कम्पोस्ट, 457 मेढ बंधान, 15 गैबियन, 6 नाली निर्माण, 48 निर्मल नीर तथा 11 अन्य कार्य चल रहे है। उन्होने बताया कि वर्तमान में जनपद पंचायत बड़वानी में 350 कार्य, निवाली में 278 कार्य, पानसेमल में 746 कार्य, पाटी में 422 कार्य, राजपुर में 822 कार्य, सेंधवा में 1516 कार्य, ठीकरी में 376 कार्य चल रहे है।

गुरुपुर्णिमा पर इंद्रटेकड़ी पर नहीं होंगे सार्वजनिक दर्शन, भंडारा भी निरस्त

माही की गूंज, खरगोन। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप दिनोंदिन बढ़ने लगा है। इससे आम जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन अब धार्मिक आयोजन भी इससे प्रभावित हो रहे है। कोरोना वायरस के चलते प्रशासन ने सामुहिक आयोजनों पर रोक लगा दी है, यही कारण है कि इस बार गुरु. शिष्य आस्था के पर्व गुरुपुर्णिमा पर इस बार सारे सार्वजनिक पुजन. हवन कार्यक्रम के साथ ही भंडारे भी निरस्त कर दिए गए है।

जिला मुख्यालय से पांच किमी दूर कसरावद रोड स्थित श्री श्री 1008 श्री पुर्णानंद बाबा (लूलाबाबा) की तपोस्थली इंद्रटेकड़ी पर भी इस बार 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर भंडारा नहीं होगा। पुर्णानंद बाबा सेवा संस्थान से जुड़े अजय भट्ट, दिलीप चौहान ने बताया कि बैडियाव के पास स्थित इंद्रटेकड़ी पर करीब 17 वर्षों से अधिक समय से भंडारे का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस से कोई संक्रमित न हों इसलिए संस्थान सदस्यों ने प्रशासन से चर्चा के बाद यहां होने वाले सार्वजनिक पुजन.अर्चन, हवन सहित भंडारे को निरस्त करने का निर्णय लिया है। यहां गुरुपुर्णिमा पर केवल मंदिर पुजारी एवं समिति से जुड़े सदस्य रामायण पाठ करेंगे, इस दिन मंदिर के पट आम श्रद्धालूओं के दर्शन के लिए बंद रखे जाएंगे, जिससे यहां भीड़ न हों और कोई वायरस की चपेट में न आएं। उल्लेखनीय है कि इंद्रटेकड़ी जिले सहित समूचे निमाड.- मालवा अंचल में श्रद्धालूओं की आस्था का केंद्र बिंदू हैं, यहां गुरुपुर्णिमा पर प्रतिवर्ष करीब डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालू दर्शन के लिए पहुंचते है।

बिना मास्क वाले दुकानदार व ग्राहकों पर बड़ी संख्या में कार्यवाही

माही की गूंज, खरगोन। मंगलवार को नगर पालिका के अमले द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बगैर मास्क लगाकर घुमने वाले व ग्राहकी करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान ग्रामीण इलाकों से शहर की ओर आने वाले तथा शहरी निवासियों के अलावा दुकानदारों पर भी चालानी कार्यवाही की गई। नपा स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते ने बताया कि मंगलवार को नपा द्वारा शहर के तीन अलग-अलग हिस्सों में दल तैनात कर आने-जाने वालों पर निगरानी की गई। इस दौरान बावड़ी बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस चौराहा व गायत्री मंदिर तिराहे के साथ-साथ एक दल बाजार में ग्राहकों तथा बिना मास्क वाले दुकानदारों के चालान बनाए गए। बिना मास्क वाले दुकानदारों से 200-200 रूपए तथा सामान्य नागरिकों के 100-100 रूपए के चालान बनाए गए। इस दौरान करीब 11 हजार रूपए के चालान काटे गए। चित्ते ने बताया कि राधा वल्लभ मार्केट में 20, सराफा बाजार में 10 और जवाहर मार्ग की 5 दुकानों के चालान तथा अन्य बिना मास्क वाले ग्राहकों के चालान बनाए गए।

प्रेम प्रसंग में ससुराल पक्ष ने विधवा पुत्रवधु को पीट-पीटकर मार डाला, प्रेमी भी घायल हुआ

माही की गूंज, बुरहानपुर।

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में निंबोला थाना अंतर्गत ग्राम रईपुरा में ससुराल पक्ष ने प्रेम प्रसंग के चलते विधवा पुत्रवधु को पीट-पीटकर मार डाला और उसके प्रेमी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पुलिस ने ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी फरार है। घटना जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर फिरोज कोटवार के खेत में हुई है। ग्राम रईपुरा में खेत में बने मकान की छत पर निवस्त्र हालत में बुरी तरह से घायल मिली महिला लीला बारेला 40 निवासी ग्राम बलडी की मंगलवार को शासकीय जिला चिकित्यालय में उपचार के दौरान मौत हो गई है। इस दौरान समीप की झांडियों में घायल मिले फकीरा 33 निवासी ग्राम बोरगांवखुर्द का जिला चिकित्यालय में उपचार चल रहा है। महिला के पति की कुछ वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। इस दौरान उसका लंबे समय से युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी ससुराल पक्ष को मिलने पर उन्होने अलग रह रही महिला को कई बार समझाने का प्रयास किया। परंतु महिला नही मानी और युवक के साथ उसकी मेल-मुलाकातें जारी है। रविवार रात बाईक पर महिला और उसका प्रेमी ग्राम रईपुरा के खेत पर पहुंचकर ठहरे थे। इस दौरान पीछा करते आए ससुराल पक्ष के लोगों ने दोनो को लकडी-डंडों से जमकर पीटा और भाग गए। सोमवार सुबह खेत पर आए मालिक ने दोनों को घायल देख उन्हे जिला चिकित्यालय पहुंचाया। मृत महिला का ससुराल गांव बोरगांवखुर्द का है।

नहीं होंगी परीक्षाएं, दिया जाएगा जनरल प्रमोशन

माही की गूंज, बड़वानी।

प्राचार्य डॉ. आरएन शुक्ल के मार्गदर्शन में निरंतर ऑनलाइन कार्यरत शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ ने बताया कि कोविड-19 के संकट के कारण मध्यप्रदेश शासन ने उच्च शिक्षा से संबंधित परीक्षाएं नहीं लेने और जनरल प्रमोशन देने का निर्णय लिया है। कार्यकर्तागण प्रीति गुलवानिया, सलोनी शर्मा, किरण वर्मा ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से अपने निर्णय की जानकारी दी। इस जानकारी के अनुसार प्रदेश के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा दिए उनके गत वर्ष/सेमेस्टर के अंकों/आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा/सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही स्नातक अंतिम वर्ष एवं चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के पूर्व वर्षों /सेमेस्टर्स में से सर्वाधिक अंक प्राप्त परीक्षा परिणाम को प्राप्तांक मानकर अंतिम वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किये जाएंगे। ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर अपने अंकों में सुधार चाहते हैं, उनके पास परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा। वे आगामी घोषित तिथि पर ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे।

कॅरियर काउंसलर डॉ. मधुसूदन चौबे ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत निर्देश और आदेश जारी होने पर उनसे भी अवगत कराया जाएगा। विद्यार्थी समय का उपयोग करते हुए अगली परीक्षाओं की या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रारंभ करें ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल बन सके।

चार विभागों को एक साथ कम्प्युटर नेटवर्क पर लाने के लिए पोर्टल तैयार

माही की गूंज, खरगोन। चार विभागों को एक साथ कम्प्युटर नेटवर्क पर लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस पोर्टल तैयार किया गया है। इन चार विभागों में न्यायालय, पुलिस, अभियोजन और जेल विभाग को शामिल किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश जाट ने बताया कि पुलिस के सॉफ्टवेयर सीसीटीएनएल, न्यायपालिका का सॉफ्टवेयर ई-कोर्ट, जेल का सॉफ्टवेयर ई-जेल और अभियोजन का सॉफ्टवेयर ई-प्रोसेक्यूशन जैसे नेटवर्क को एक साथ जोड़ा गया है। ऐसा होने से जिले एवं तहसील न्यायालयों में अभियोजन अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रकरणों की जानकारी तथा लिगल ऑपीनियन/केस डायरी की ऑनलाईन जानकारी का इंद्राज होने से प्रतिदिन की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस कार्य के लिए लोक अभियोजन संचालनालय के आदेशानुसार जिले में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश जाट को नोडल अधिकारी एवं लिपिक महेंद्र कुमावत व रश्मि यादव को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है।

मृतक शिक्षक की पत्नि को सौपा गया 50 हजार अनुगृह की राशि का पत्रक

माही की गूंज, बड़वानी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विवेक पाण्डेय ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित बैठक के दौरान शासकीय प्राथमिक विद्यालय बहेड़िया के मृतक शिक्षक कैलाश पाटील की पत्नि कोमल पाटील को 50 हजार रूपये की स्वीकृत अनुगृह राशि के दस्तावेज सौपे है।

अज्ञात आरोपी पर 5 हजार रूपए का इनाम किया घोषित

माही की गूंज, खरगोन। पुलिस अधीक्षक सुनील पांडेय ने अज्ञात आरोपी पर 5 हजार रूपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 सितंबर 2011 को थाना सनावद में फरियादी मोहम्मद पिता फैज मोहम्मद निवासी मछली बाजार सनावद की सूचना पर 482/2014 धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान अपहृता व अज्ञात आरोपी की तलाशी प्रारंभ की गई। अपहृता बालक एवं फरार आरोपी के हर संभव प्रयास किए, लेकिन अज्ञात आरोपी अब भी फरार है। पुलिस अधीक्षक पांडेय ने कहा कि फरार आरोपी को बंदी बनवाने या उसकी सही सूचना देने वाले व्यक्ति को घोषित 5 हजार रूपए का इनाम दिया जाएगा।

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

माही की गूंज, खरगोन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने पुलिस अधीक्षक सुनील पांडेय के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार संपूर्ण जिले की राजस्व सीमा के महत्वपूर्ण संस्थान जैसे- ज्वेलरी शॉप, शोरूम, अन्य वित्तीय संस्थान तथा सराफा दुकानें, जनरल स्टोर्स आदि अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाएं तथा उन्हें चालू स्थिति में रखें। प्रत्येक आने वाले ग्राहक के दुकान, वित्तीय संस्थान पर आने की स्थिति में प्रथम बार उसका मास्क उतरवाकर चेहरा रिकार्ड करवाने के उपरांत वापस लगवाया जाएं। यह आदेश 22 जून से लागू हो चुका है, जो 20 अगस्त 2020 तक के लिए प्रभावशील रहेगा।

बहिष्कार नही, बड़ी लकीर खीचे

कोविड-19 के इलाज में हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन की भूमिका वाला अध्याय अब खत्म हो चुका है। लेकिन इस समय उसे याद करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दो महीने पहले, जब अचानक इस दवा की मांग उठी, तो पता चला कि पूरी दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। उस समय तक शायद ज्यादातर भारतीय भी इसे नहीं जानते थे। बढ़ी मांग का अर्थ था कि भारतीय कंपनियां इसका उत्पादन तेजी से बढ़ाएं, तभी पता लगा कि इस दवा का उत्पादन करने वाली भारतीय कंपनियां कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर हैं। यह अकेला प्रकरण हमें कई चीजें बताता है। फिलहाल यहां हम ग्लोबलाइजेशन के उस अद्भुत अपूर्व स्वप्न की बात नहीं करेंगे, जो यह कहता रहा है कि कारोबार के मामले में पूरी दुनिया एक है, असली चीज है बाजार और इसमें मेरा, तेरा, उसका की बात नहीं होनी चाहिए।

हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन के बाजार में भारत की बादशाहत करीब ढाई दशक पुरानी उस नीति से उपजी थी, जिसमें यह तय किया गया था कि भारत को अब गैर-पेटेंट दवाओं के कारोबार का बड़ा खिलाड़ी बनना है। और कुछ ही समय में हम बल्क ड्रग कारोबार के सबसे बड़े खिलाड़ी बन भी गए। इस कामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण हम ईरान में देख सकते हैं। दशकों से चली आ रही अमेरिकी पाबंदियों के दौरान ईरान की सबसे बड़ी समस्या दवाओं को लेकर रही है। भारत से निर्यात होने वाली दवाओं ने न सिर्फ उसकी इस जरूरत को पूरा किया है, बल्कि इस दौरान वहां लाखों लोगों की जान भी बचाई। बल्क ड्रग कारोबार में कामयाबी दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो दवाओं की गुणवत्ता और इसी के साथ स्पर्द्धा वाले बाजार में उनकी कम कीमत। गुणवत्ता के मामले में तो भारतीय कंपनियों ने महारत हासिल कर ली, लेकिन कीमत कम रखने के लिए सस्ता कच्चा माल चीन में ही आसान विकल्प था, इसलिए यह कारोबार कई मामलों में चीन पर निर्भर हो गया।

दूसरे शब्दों में कहें, तो कामयाबी की हमारी इस कोशिश में चीन ने भी एक भूमिका निभाई। और अगर इसी को अलग तरह से देखें, तो चीन आज जिस तरह से आर्थिक ताकत बना है, उसमें अपने सपनों के लिए चीन पर हमारी निर्भरता की भी एक भूमिका है। पिछले तीन दशक में दुनिया के तमाम विकसित और विकासशील देशों को इस तरह की निर्भरताएं देता हुआ चीन लगातार आगे बढ़ता गया है। पर क्या अब उसके उत्पादों और उसकी कंपनियों के बहिष्कार से चक्र को उल्टा घुमाया जा सकता है?

यह सवाल इस समय इसलिए जरूरी है कि पूरा सोशल मीडिया चीन और उसके उत्पादों के बहिष्कार की अपीलों से पटा पड़ा है। यह सिलसिला कोरोना संकट के पैदा होने के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन सीमा पर उसकी आक्रामकता ने इसे बढ़ा दिया और पिछले मंगलवार को जब यह खबर आई कि लद्दाख के गलवान क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की टुकड़ी पर हमला बोलकर 20 की जान ले ली, तब से यह शोर सातवें आसमान पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर ऐसा उबाल जल्द ही बेहूदगी की हद तक पहुंच जाता है। हैशटैग बायकॉट चाइना के तहत पहले चीन में बने फोन और टीवी तोड़ने के वीडियो शेयर किए गए, फिर एक संदेश यह भी आया कि गुजरात में नमर्दा नदी के तट पर बनी सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा को हटा लेना चाहिए, क्योंकि उसका निर्माण एक चीनी कंपनी ने किया है।

मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए भारत सरकार ने अपने आप को ऐसे किसी उबाल से दूर रखा है। एकाध केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने इससे सुर मिलाने की कोशिश जरूर की। इस बीच कुछ चीनी कंपनियों के ठेके जरूर रद्द हुए हैं, जिसे सरकार की मंशा के रूप में भी पेश किया जा रहा है। वैसे यह पहला मौका नहीं है, जब चीन के उत्पादों के बहिष्कार पर उबाल दिखा हो। यही डोका ला विवाद के समय भी हुआ था और यही तब भी हुआ था, जब मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का साथ दिया था। इसके बावजूद भारतीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी बढ़ती रही।

क्या इस बार बहिष्कार की यह मुहिम चीन की अक्ल ठिकाने लगाने में कामयाब हो सकेगी? क्या सीमा पर चीन की हिमाकत का यही सही जवाब है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बहिष्कार का यह रास्ता भारत को एक बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की ओर ले जाएगा? यह तीसरा सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहिष्कार के तर्कों में अक्सर सारा जोर इसी पर होता है।

कोई भी देश बड़ी आर्थिक ताकत कैसे बनता है? इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे पहले चीन का उदाहरण ही लेते हैं। चीन पूरे माओ युग में बहिष्कार वाला देश था। लंबे समय तक उसने पश्चिमी उत्पादों का बहिष्कार किया। वह ताकत तो था, लेकिन आर्थिक ताकत नहीं। आर्थिक ताकत वह बहिष्कार के युग से बाहर निकलने के बाद ही बना। इससे अच्छा उदाहरण जापान का है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर सिर्फहिरोशिमा और नागासाकी को ही बरबाद नहीं किया, बल्कि जापान के अहं और गौरव को भी भारी ठेस पहुंचाई।

हरजिंदर, वरिष्ठ पत्रकार

बाद में जब आर्थिक तरक्की का युग शुरू हुआ, तो जापान ने कभी अमेरिका के बहिष्कार की बात नहीं की, लेकिन बाजार के खेल में उसने अमेरिका को मात दे दी। तरक्की का रास्ता बहिष्कार से नहीं, ज्यादा बड़ी लकीर खींचने से निकलता है। बहिष्कार करके आप खुद को ही उस रेस से बाहर कर लेते हैं, जिसे दरअसल आप जीतना चाहते हैं।

एक उदाहरण वालमार्ट का है। वालमार्ट भारत में न आए, इसके लिए कई राजनीतिक दलों ने जी जान लगा दी थी। हालांकि पिछले दरवाजे से वह चली आई। चीन में ऐसा नहीं हुआ। वालमार्ट बिना किसी विरोध के चीन में आई और उसने सैकड़ों स्टोर खोलकर वहां छाने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही चीन की कुछ कंपनियों ने ज्यादा बड़ी लकीर खींच दी। इस समय चीन के संगठित रिटेल बाजार में वालमार्ट पांचवें नंबर की कंपनी है और चीन की अलीबाबा दुनिया के रिटेल बाजार की नंबर एक कंपनी बन चुकी है।

फिलहाल हमारे सामने दोनों रास्ते खुले हैं- चीन के उत्पादों का बहिष्कार या उससे बड़ी लकीर खींचना।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नामांतरण के लिए ऑनलाईन करें आवेदन

माही की गूंज, खरगोन। नामांतरण के लिए अब किसी भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व से संबंधित प्रकरणों के ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिए रेवेन्यु केस मेनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इस प्रक्रिया से संबंधित जानकारी का यूजर मेन्युअल भी तैयार किया गया है। पटवारियों और पंचायत सचिवों को इसका प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। कोई भी व्यक्ति वेबसाईट ॅ.तबउे.उच.हवअ.पद पर स्वयं, एमपी ऑनलाईन कियोस्क, लोक सेवा केंद्र, पटवारी अथवा पंचायत सचिव के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। आवेदक को आवेदन की पावती भी ऑनलाईन मिलेगी।

यह है नामांतरण के प्रकार

फौती नामांतरण, सभी वारिसों के हक के आधार पर- खातेदार की मृत्यु होने के उपरांत उसके वैध वारिसों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना। फौती नामांतरण, कुछ वारिसों के हक त्याग के साथ-साथ- खातेदार की मृत्यु होने के उपरांत जिन वारिसों ने अपना हक त्याग कर दिया है उन्हें छोड़ कर शेष वैध वारिसों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना। फौती नामांतरण, वसीयत के आधार पर- खातेदार द्वारा जीवनकाल में वसीयतनामा करने पर उसकी मृत्यु के बाद उसके आधार पर नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना। पंजीकृत विक्रय-पत्र के के आधार पर क्रेता के नाम नामांतरण। पंजीकृत दानपत्र के आधार पर- खातेदार द्वारा अपनी भूमि को अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य को बिना प्रतिफल लिए हस्तांतरित करना। पंजीकृत विनिमय पत्र के आधार पर-पंजीकृत विनिमय पत्र के आधार पर भूमि की अदला-बदली। व्यवहार न्यायालय के डिक्री के आधार पर- व्यवहार न्यायालय द्वारा भूमि को खातेदार के स्थान परसय अन्य व्यक्ति के नाम किए जाने का आदेश। नाबालिक से बालिक होने पर-खातेदार के वयस्क (बालिक) हो जाने पर रिकार्ड का अद्यतन। बटाई/बंधक दर्ज करने के लिए- भूमि पर बैंक से ऋण लिए जाने के उपरांत भूमि को बंधक करना। बटाईध्बंधक विमुक्त करने के लिए-ऋण वापस जमा करने उपरांत भूमि को विमुक्त किया जाना। किसी अन्य प्रकार से हक अर्जन द्वारा- ऊपर वर्णित प्रकारों से भिन्न प्रकार से हक अर्जन होने पर भी ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

भारतीय संस्कृति के साथ गायत्री शक्ति पीठ व गायत्री परिवार की व्यवस्थाओं को भी पंडित मीत भवानी कश्यप ने किया दागदार

मामलाः एक ही गोत्र के होकर भुआ-भतीजे की शादी का, जिसमें शादी किसी और ने करवाई तो प्रमाणिकरण किसी ओर ने दिया

माही की गूंज, झाबुआ।

आज हम ऐसे कर्मकांठी पंडित की दास्तां उजागर कर रहे हैं, जिसने लक्ष्मी के मोह में भारतीय संस्कृति के साथ गायत्री शक्तिपीठ, गायत्री परिवार व धार्मिक संस्थानों को ही कलंकित कर धूमिल करने का प्रयास किया है।

शपथ-पत्र के विपरीत, माता-पिता की अनुपस्थिती में लालची पंडित मीत भवानी कश्यप ने शादी को किया प्रमाणित तो शादी किसी ओर पंडित ने करवाई।

उक्त शादी का प्रमाणित प्रमाण-पत्र गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञा संस्थान के नाम से दिया हुआ प्रमाण-पत्र।

गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार संस्थान से जुड़े अनुयायी भारत ही नहीं वरन विश्व के कई देशों के लोग भी जुड़े हुए हैं और गायत्री परिवार भारतीय संस्कृति के अनुरूप चल वैदिक संस्कारों व शिक्षा का संदेश देने के साथ ही सतमार्ग पर चलने व दुर्गम मार्ग को छोड़ने के उद्देश्य के साथ आज गायत्री परिवार से जुड़ी कई संस्थाएं गांव-गांव व देश-विदेश में होकर लाखों लोग जुड़े है और वे किसी भी अनैतिक कार्य का समर्थन नहीं करते है। परंतु कोई व्यक्ति वह भी एक पंडित होकर व कर्मकांठी होकर गायत्री परिवार तथा गायत्री शक्तिपीठ से जुड़कर संस्थान के सिद्धांतों के विपरीत जाकर कार्य करता है, तो तय है धार्मिक संस्थान की पूरी व्यवस्थाऔ को भी धूमिल करता है।

ऐसा ही भारतीय संस्कृति, गायत्री परिवार संस्थान व गायत्री शक्तिपीठ को कलंकित करने का कृत्य गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञा संस्थान रविंद्र नगर, इंदौर से जुड़े पंडित मीत भवानी कश्यप ने भारतीय संस्कृति एवं गायत्री परिवार संस्थान के उदेश्यों को अपने स्वार्थ के चलते धूमिल करने का कृत्य किया है। बता दें कि हमने पूर्व में 30 अप्रैल को 'परिवार के प्रभुत्व की विचारधारा को अमलकर अपने ही परिवार की भुआ को भतीजा लेकर भागा', 'कलयुगी युगल भुआ-भतीजे ने गरबा डान्स का किया वीडियो वायरल, लड़की के माता-पिता है मानसिक तनाव में' व 4 जून को 'दो कुल की तारणहार होती है लडकिया, पर कलयुगी उर्वशी ने अपने कुल के साथ भारतीय संस्कृति को भी किया कलंकित', 'लड़के के परिवार उक्त रिश्ते को मान्यता देकर समाज व भारतीय संस्कृति से भी अपने-आप को मान रहे बडा' शीर्षक के साथ गूंज मे समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें राणापुर स्व. श्री लुणाजी पडियार परिवार के वंशज व एक ही गोत्र व परिवार के होकर जोबट निवासी निर्भय पडियार की लड़की उर्वशी व थांदला निवासी कमलेश पडियार का लड़का हार्दिक भाग गए। जो कि रिश्ते में भुआ-भतीजे होकर जिन्होंने भारतीय संस्कृति, सामाजिक एवं कानून सभी मर्यादाओं का हनन कर 21 मार्च को विवाह रचाया और इस विवाह का समर्थन लड़के परिवार के पिता कमलेश व काका किशोर एवं परिवार ने किया।

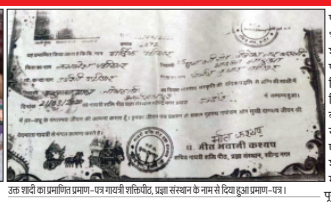

हिंदू संस्कृति के साथ अपने ही कुल व समाज को कलंकित करने वाला उक्त युगल की शादी आखिर कैसे और किसने करवाई की गूंज ने जानकारी निकाली तो, पता चला कि, 20 मार्च को उप पंजीयक कार्यालय सुखलिया, इंदौर के अंतर्गत जयश्री कुमारे स्टांप वेंडर से 100 रूपए का स्टांप उर्वशी पडियार ने खरीदा और नोटरीकर्ता के समक्ष शपथ-पत्र 1 से 12 पॉइंट तक लिखा। शपथ-पत्र में दर्शाया कि बालिग होकर पूर्ण वयस्क है तथा अपने जीवन एवं भविष्य के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में समर्थ है, मैं हिन्दु धर्म की अनुयायी हूं तथा हिन्दु धर्म को मानती हूँ, मैं हार्दिक पडियार से विवाह करने के समर्थन में शपथ-पत्र बिना किसी के डराए-धमकाए और न ही कोई जोर अथवा दबाव मुझ पर डाला है।

उक्त विवाह में हम दोनों के परिवारजनों की पूर्ण सहमति व अनुमति है, उक्त बात पाइंट नंबर 7 में दर्शाया है। वही पाइंट नंबर 11 में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार गायत्री मंदिर/आर्य समाज मंदिर में विवाह करेंगे दर्शाया। शपथ-पत्र में पाइंट क्रमांक 9 का उल्लेख ही नहीं है। शपथ-पत्र अनुसारः-

1- उक्त विवाह में लड़के-लड़की दोनों के परिवारजनों की पूर्ण सहमति व अनुमति है।

2- हिंदू रीति-रिवाज अनुसार गायत्री मंदिर/आर्य समाज मंदिर में विवाह करेंगे।

3- हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तथा हिंदू धर्म को मानते है।

उक्त शपथ के साथ ही कलंकित करने वाला यह विवाह फर्जी एवं अमान्य ही माना जा सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में एक ही नाते-रिश्तेदार में विवाह करना प्रतिबंधित है तो, वहीं उक्त विवाह में दोनों परिवार की सहमति व अनुमति थी, तो तय है शपथ-पत्र अनुसार दोनों के माता-पिता एवं परिवार विवाह स्थल पर मौजूद होना थे, परंतु लड़की के माता-पिता या परिवार का एक भी सदस्य उक्त विवाह स्थल पर उपस्थित नहीं था। तो वही लड़के के पिता और काका भले ही उक्त विवाह को समर्थन दे रहे हैं, फिर भी वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि शादी के दौरान वह उपस्थित नहीं थे। तो वही उनकी अनुपस्थिति में व हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार एक नाते परिवार में विवाह करना अनुचित है तो, आखिर किस आधार पर, किस विद्वान पंडित ने शपथ-पत्र के ही विपरीत जाकर विवाह करवाया वरन प्रमाण-पत्र देकर शादी का प्रमाणीकरण भी किया।

उक्त प्रमाणिकरण की जानकारी निकाली तो फर्जी एवं कलंकित करने वाली शादी को प्रमाणित करने वाले पंडित मीत भवानी कश्यप, जिन्होंने सचिव गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञा संस्थान रविंद्र नगर इंदौर की सील एवं गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञा संस्थान रविंद्र नगर, इंदौर की पंजीकृत मोहर लगाकर विवाह को भारतीय संस्कृति की वैदिक पद्धति से अग्नि की साक्षी में 21 मार्च 2020 को गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञा संस्थान रविंद्र नगर, इंदौर में संपन्न हुआ का प्रमाणित प्रमाण-पत्र दिया।

यह प्रमाण-पत्र कहां तक सही एवं प्रमाणित है की जानकारी निकालने हेतु पंडित मीत भवानी कश्यप से मो. 7869044382 पर संपर्क किया और जानकारी मांगी कि, हिन्दु संस्कृति में तथा किस वैदिक ग्रंथ के आधार पर एक ही नाते-रिश्तेदार भुआ-भतीजे का विवाह करवाया और शपथ-पत्र में माता-पिता व परिवार की अनुमति थी तो, विवाह के दौरान कौन से माता-पिता को उपस्थित कर विवाह करवाया? गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञा संस्थान के पास शादी करवाने एवं उसे प्रमाणित करने का कोई शासकीय पंजीयन है? तो पंडित मीत भवानी कश्यप ने 8 जून के पूर्व लॉकडाउन का बहाना बनाकर कहां, 8 जून को मंदिर खुलने के बाद 9 या 10 जून को विवाह संबंधित पूरी जानकारी दे दूंगा। साथ ही कहा कि यह संस्था रजिस्टर्ड है और लड़के-लड़की ने फ्रोड किया या मेरे पास फर्जी मां-बाप को लाकर शादी करवाई तो मैं खुद उनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाउंगा।

जिसके बाद पंडित ने उक्त फर्जी शादी की जानकारी देने से बचने के लिए गूंज के प्रतिनिधि का मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर दिया। जिसके बाद अन्य मो.नं. से चर्चा कि तो पंडित चोर की दाढ़ी में तिनके की तर्ज पर ऐसा बौखला गया कि उसने मीडिया को जानकारी देने से इंकार कर दिया। वहीं जब गायत्री परिवार के अनुयायी के माध्यम से उक्त पंडित की हकीकत जानी तो पता चला, गायत्री परिवार एवं गायत्री शक्तिपीठ के पास इस तरह से शादी करवाने व शादी का प्रमाणिकरण करवाने का कोई शासकीय-अशासकीय अधिकार ही नहीं है।

उक्त पंडित पूर्व में गायत्री परिवार व गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञा संस्थान से जुडा अवश्य था लेकिन संस्था के नाम पर उक्त लालची पंडित ने अपना व्यवसायिक धंधा बना लिया था, जिसके चलते गायत्री शक्तिपीठ के सदस्यो ने संगठनात्मक रूप से निर्णय लेकर उसे गायत्री परिवार से हटा दिया गया था, जिसके कारण गायत्री परिवार की किसी भी गतिविधि में अब लालची पंडित कश्यप को आमंत्रित नहीं किया जाता है।

गायत्री परिवार के हमारे सूत्र ने बताया कि पंडित कश्यप के पास पुराने कोई दस्तावेज पड़े होंगे जिसका उपयोग उसने किया होगा। गायत्री शक्तिपीठ व गायत्री परिवार इस प्रकार का कोई भी प्रमाणीकरण नहीं करती है। वही शादी का वीडियो जारी हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि शादी करवाने वाला पंडित कोई और है और शादी को प्रमाणित करने वाला पंडित कोई और है।

विधायक भूरिया ने 30 लाख रूपए की नवीन डीपी का शुभारंभ किया

माही की गूंज, झाबुआ। मैं झाबुआ विधानसभा का जनप्रतिनिधि हूं तथा मेरी प्राथमिकता है कि क्षेत्र का विकास हो, विकास हेतु मै कटिबद्ध हूं। उक्त बात क्षेत्रीय विधायक कांतिलाल भूरिया ने अपने अथक प्रयास के चलते झाबुआ विधानसभा में विकास की गंगा बहाते हुए अपने क्षेत्र में अनेक विघुत डी पी के शुभारंभ के अवसर पर कही है। श्री भूरिया ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है, उसे पुरा करने में पूर्ण विश्वास रखती है। तथा कांग्रेस पार्टी एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा किये गये कार्य धरातल पर दिखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपने शासनकाल के दौरान क्षेत्रीय विधायकों के साथ सहयोग कर जिले में करोड़ों के विकास कार्य किये गए हैं। जिसका लाभ जिलेवासीयों को मिलने लगा है, उसी कड़ी में झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना वर्ष 2019-20 के द्वारा अनुशांसित प्रस्ताव तथा विधायक प्रतिनिधि डॉ. विक्रांत भूरिया एवं जिला कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष भटट ने जानकारी देते हुए बताया कि झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में रानापुर जनपद पंचायत अन्तर्गत 30 लाख से अधिक की राशि विद्युतीकरण के अन्तर्गत नवीन डीपी लगाने हेतु स्वीकृती की गई जिसका कार्य विगत मार्च माह से चल रहा था। नवीन डीपी लगाने से झाबुआ विधानसभा की पंचायतों को लाभ मिलेगा। उक्त डीपी लगने से क्षेत्र में जहां सिंचाई का लाभ किसानों का प्राप्त होगा साथ ही उनकी आमदानी बढेगी बच्चों को शिक्षा में अंधेरे में नहीं शिक्षा ग्रहण करना पडेगी साथ ही आम जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। अपने उद्बबोधन में डॉ विक्रान्त भूरिया ने कहा कि आगामी दिनो में ओर विधायक महोदय द्वारा स्वीकृत विघुत डीपी का भी शुभारंभ किया जावेगा तथा कांग्रेस पार्टी क्षेत्र विकास हेतु कटिबद्ध है।सम्पूर्ण विधानसभा में आगामी दिनों में ऐसे ही जन हितैषी कार्य किये जावेगें, विघुतिकरण एवं सिंचाई,शैक्षणिक के कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर कार्य किये जावेगें।

विधायक कांतिलाल भूरिया ने अपने एक दिन के तुफानी दौरे में ग्रामीणों के बीच पहुंच कर ग्राम पंचायत धामनीनाना भूरिया फलिया में विद्युतिकरण नवीन डीपी निर्माण लागत 4.06 लाख, धामनीचमना अजनार फलिया में विद्युतिकरण नवीन डीपी निर्माण लागत 4.27 लाख, उबेराव नया फलिया में विद्युतिकरण नवीन डीपी निर्माण लागत 3.80 लाख, ग्राम पंचां मोहनपुरा ग्राम चुलिया बड़ी दलसिंह फलिया में विद्युतिकरण नवीन डीपी निर्माण लागत 3.25 लाख, अंधारवड़ कहुड़ा कंजा फलिया में विद्युतिकरण नवीन डीपी निर्माण लागत 4.06 लाख, डाबतलाई मोहनीया फलिया में विद्युतिकरण नवीन डीपी निर्माण लागत 3.31 लाख, ढोल्यावड़ बड़ा फलिया में विद्युतिकरण कार्य हेतु पोल लागत 4.89 लाख, बन सोलिया फलिया में विद्युतिकरण नवीन डीपी निर्माण लागत 2.91 लाख, छापरखंडा तड़वी फलिया में विद्युतिकरण नवीन डीपी निर्माण लागत 4.17 लाख रूपये आदि कार्यो का शुभांरभ किया गया। इस अवसर पर रानापुर जनपद पंचायत क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के चन्दु पडियार, कनु बसेर ने भी सम्बोधित किया तथा क्षेत्र के सरपंच खुमानजी, मोहन डामोर, धुमाजी, गोपाल जी,अमरसिंह, रकसिंह ढोल्यावड,दलसिंह, वीरसिंहजी, धमेन्द्र सोलिया, विनय भाभोर तथा अन्य ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि तथा क्षेत्र के युवा कांग्रेसी उपस्थिति थे।

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों तथा बिजली बिलों लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, झाबुआ। वर्तमान में मध्यप्रदेष में मंहगाई की मार से पुरा देश त्रस्त है। वर्तमान में प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल के दाम लगातार बढ रहे है। मंहगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि करना जनता के साथ कुठाराघात है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देशानुसार आज दोपहर 1:30 बजे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल मेहता के नेतृत्व में एवं विधायक प्रतिनिधि डॉ. विक्रांत भूरिया सहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने पेट्रोल डीजल दामों में लगातार वृद्धि के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर प्रबल सिपाहा को ज्ञापन सौंपा। वर्तमान समय में पूरे देश में कोरोना माहामारी सक्रमण के कारण धारा 144 का पालन करते हुए कांग्रेस पदाधिकारीयों ने सोशलडिस्टेंसींग का पालने किया तथा सिमित संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ज्ञापन का वाचन जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता ने किया। इस अवसर पर निर्मल मेहता ने कहा कि कोरोना महामारी से आर्थिक तंगी बढ़ती बेरोजगारी वह महंगाई की मार से पहले ही आम जनता भारी परेशानी का सामना कर रही है ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि से आम जनता पर दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तेल की कीमतों में से वृद्धि में आम जनता की कमर तोड़ दी है पूर्व में कच्चा तेल 66 रू प्रति बैरल था तो सरकार ने 16 टैक्स बढ़ा दिया पिछले 6 माह से क्रूड आयल की कीमत आधी रह गई है लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है जो कि देश की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है देश प्रदेश में कोरोना के प्रकोप एवं लगातार लॉकडाउन के चलते एंव कोरोना संक्रमण वृद्धि के कारण चारों और बेकारी आर्थिक तंगी व महँगाई का तांडव हो रहा है ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई का और बोझ बढ़ा रही है, पूरा देश कोरोना महामारी के चलते अभूतपूर्व स्वास्थ्य आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में भी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बार बार बढ़ाने का असंवेदनशील फैसला लिया है जब देश में महामारी के चलते करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी है काम धंधे बंद हो गए हैं और मध्यम वर्ग की आमदनी में तेजी से गिरावट आ रही है यहा तक की खरीफ के सीजन में किसान फसल बुवाई मैं मुश्किलों का सामना कर रहा है ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना गलत है।

इस अवसर पर जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि विक्रान्त भूरिया ने बताया कि मध्यप्रदेश के 52 जिलों में पेट्रोल के दाम 87.71 से लेकर 89.45 रू. है। अनुपपुर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल 89.45 रू. बिक रहा है। प्रदेश में 6 जून 2020 से 23 जून तक पेट्रोल में 10.67 रू. डीजल में 10.12 रू. प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। अप्रेल एवं मई 2020 में प्रदेश में पेट्रोल 77 रू. प्रति लिटर एवं डीजल 68 रू. के लगभग बिक रहा था। पेट्रोल एवं डीजल की बढती कीमतों का कांग्रेस पार्टी नें विरोध करती है।

पेट्रोल एवं डीजल की बढती कीमतों के कारण देश प्रदेश में महंगाई बढती जा रही है तथा लोगों की आमदानी में बेहताशा कमी होती जा रही है जिस कारण कई परिवार भूखों मरने तक की नौबत आ चुकी है। म.प्र. में विद्युत विभाग ने भी लोगों को भारी भरकम बिल देकर लोगों की परेशानीयों को ओर बढा दिया है। किसानों को वर्तमान में खाद बीज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बाजार में नकली खाद एवं बीज उचें दामों पर बेचा जा रहा है। म.प्र. की भाजपा सरकार कुभंकरणी की नींद सो रही है।

जिला कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष भटट ने बताया कि उक्त ज्ञापन म.प्र. कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधीजी ने भी मोदी सरकार से पेट्रोल एवं डीजल के कीमतों में वृद्धि को रोकने की मांग की थी साथ ही उन्होने मांग की थी कि कोरोना महामारी के कारण कई परिवार अभी भी गरीबी से झूझ रहे है, ऐसे में पूर्व में तीन माह का राशन गरीबों को निशुल्क वितरण किया गया था उसी प्रकार आगामी तीन माह हेतु भी निशुल्क राशन गरीबों को वितरण किया जावे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति डामोर, जिला कांग्रेस प्रवक्ता आचार्य नामदेव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गोरव सक्सेना, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पेटलावद नरेन्द्रपाल सलुनिया, जिला कांग्रेस महामंत्री जितेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री, कांग्रेस पदाधिकारी राजेश भटट्, मानसिंह मेड़ा, राजेश डामोर, आशिष भूरिया, पार्षद रसिद कुरेशी, हेमेन्द्र कटारा, कांग्रेस नेता प्रकाश जैन विजय भाबोर, जितेन्द्र शाह, दीपू डोडियार, नितेश डामोर, धुमा डामोर, रोहित हटिला, अरूण मकवाना आदि उपस्थित थे।

भाजपा मंडल रामा ने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए

माही की गूंज, झाबुआ। रामा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओ के द्वारा डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस कोरोना महामारी के चलते बडे ही सादगी से मनाया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओ ने मंडल अध्यक्ष बापूसिह भूरिया के नेतृत्व मे डॉ मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके किये गये कार्यो को याद किया। वरिष्ठ अभिभाषक उत्तम जैन ने डॉ मुखर्जी को याद करते हुय कहा कि एक देश एक निशान एक प्रधन के संकल्पो को पुरा करने के लिए स्वयं का बलिदान देने के लिए उन्हे याद किया जाता है। कश्मीर में धारा 370 को लेकर उनका विरोध मुखर था। इस अवसर पर कांतिलाल डावर, पंकज कोठारी, कुवरसिंह भूरिया, करणसिंह अमलियार, पानसिंह राठौरे, सुनील भूरिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पिछले कई दिनों से फैल है बैंक की लिंक

बैंक ऑफइंडिया के बाहर लगी भीड़, आठ दिन से खाताधारक और व्यापारी परेशान

माही की गूंज, पेटलावद। पेटलावद में बामनिया रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की लिंक पिछले 08 दिनों से भी अधिक समय से बंद पड़ी है। जिससे बैंक के सैकड़ों खाताधारकों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है यहाँ बहार से आने वाले ग्रामीणों को बैंक में आने के बाद पता चलता है की लिंक होने की सूचना मिलती है तो घंटो बैंक के बाहर बैठकर इंतजार कर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, न बैंक की और से पानी की कोई व्यवस्था है न ही बैठने की, कृषि के समय मे किसानों को खाद बीज के लिए पैसों की आवश्यकता है वही व्यापारी को माल के पैसे अन्य व्यापारियों को बैंक से ट्रांसफर करने होते है और बैंक से जुड़े कई व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, वही लगातार 08 दिन से लिंक फैल होने से बैंक के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही हैं और शोसल डिस्टेंसी की धज्जियां भी उड़ रही है वही बैंक का कहना है कि बीएसएनएल की लाइन खराब होने के कारण परेशानी आरही हैं, जबकि बीएसएनएल के जिलाधिकारी को इस बारे में कोई जानकारी नही है उनका कहना है कि पेटलावद के एसडीओ से बात करते के बताता हूं। बैंक के अधिकारी लापरवाही बरते कर बैठे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोज पेट्रोल फूंक कर पेटलावद आने पर मजबूर हैं, ग्राम दुलाखेड़ी की शांति बाई, जमना, टेमरिया के रादु आदि ने बताया कि हम रोज बैंक आते हैं लेकिन हमको बैंक में नही जाने दिया जाता और लिंक फेल है बोल कर बाहर धूप में दिन भर बिठाया जाता है, ओर शाम को कहा जाता है कल आना जिससे हम लोग परेशान हो रहे हैं पिछले 08 दिन से रोज आ रहे हैं कई लोगो के खाते जमा पैसे से ज्यादा खर्च हो गए हैं लेकिन पैसे नही मिले।

स्वर्गीय दिलीपसिंह भूरिया की 5 वीं पुण्यतिथि पर किया स्मरण

भाजपा - कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित पूरे अंचल ने दी भूरिया को श्रद्धांजलि

माही गूंज, झाबुआ।

पूरे देश भर में आदिवासी समाज को उनके अधिकारों के लिए सतत जुझारू पन के साथ काम करने का जज्बा पालने वाले क्या हुआ रतलाम संसदीय सीट से 6 बार सांसद निर्वाचित होने वाले आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की पांचवी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें बुधवार को मेघनगर नाका स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूरे संसदीय क्षेत्र की ओर से उन्हें भाव विह्वल श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर रतलाम झाबुआ के सांसद गुमान सिंह डामोर पूर्व विधायक एवं श्री भूरिया की पुत्री सुश्री निर्मला भूरिया पूर्व विधायक कल सिंह भाबर,शांतिलाल बिलवाल,जिला भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक शैलेश दुबे विजय नायर,दौलत भावसार, महामंत्री श्यामा ताहड़,प्रवीण सुराणा,प्रफुल्ल गादीया ,भानु भूरिया, सहित जिलेभर से आए सभी भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं एवं मंडल के अध्यक्षों की उपस्थिति में श्री भूरिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई की गई।

सांसद गुमानसिह डामोर स्वर्गीय दिलीपसिंहजी की प्रतिमा पर पुष्पाजंली अर्पित करते हुए।

स्व. दिलीपसिंह भूरिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुये डॉ विक्रांत भूरिया एवं कार्यकर्ता।

इस अवसर पर बोलते हुए सांसद गुमानसिंह डामोर ने श्री भूरिया की राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए उन्हें जुझारू व्यक्तित्व का धनी बताते हुए उन्हें सहकारिता क्षेत्र का पितृ पुरुष बताया। श्री डामोर ने कहा कि दिलीपसिंह भूरिया ने पूरा जीवन गरीबो,शोषितो,को उनके अधिकार दिलाने में अर्पित कर दिया।श्री डामोर ने स्व, भूरिया को स्मरण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

पूर्व विधायक सुश्री निर्मला भूरिया ने अपने पिता स्व, दिलीपसिंग भूरिया को स्मरण करते हुए मछलिया से राष्ट्रीय राजनिति तक जिक्र करते हुए माही परियोजना को साकार करने का श्रेय देते हुए अपने संस्मरण साझा किए। सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि श्री भूरिया आदिवासियों के विकास में शराब को बहुत बड़ा रोड़ा मानते थे।जिन्होंने शराब बंदी का समर्थन किया था। जिला भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक ने श्री भूरिया को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें देश के आदिवासियों का सर्वमान्य नेता बताते हुए सामाजिक,न्यायिक ओर धार्मिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पैसा कानून भूरिया कमेटी के प्रमुख के रूप में बनाया था जो आज कानूनी तौर पर देश भर में लागू है। 2001 में ततकालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपई ने उन्हे राष्ट्रीय जन जाती आयोग का अध्यक्ष का दायित्व सौपा था। श्री भूरिया को पांचवी पूण्य तिथि पर सोशल डिस्टेंसिइंग का पालन करते हुए श्री भूरिया को स्मरण किया गया।

कांग्रेसजनों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कियां स्मरण

बुधवार को रतलाम संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद एवं आदिवासी नेता स्वर्गिय दिलिपसिंह भूरिया की 5वी पूण्यतिथि पर जिला कांग्रेस के पदाधिकारीयों ने मेघनगर नाका स्थित स्वर्गीय दिलिपसिंह भूरिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें स्मरण किया। युवा नेता डॉ. विक्रांत भूरिया ने इस अवसर पर कहा कि वे आदिवासी नेता के रूप में हमेशा याद किये जायेंगे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रह कर सांसद के रूप अनेक विकास कार्य किये। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव सक्सेना, जिला कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष भटट्, आशिष भूरिया, पार्षद रसीद कुरेशी, कांग्रेस नेता जितेन्द्र शाह, विजय भाबोर, बंटी डामोर, रोहित हटिला आदि कार्यकर्ता विशेष रूप से उपस्थित थे।

पिता-पुत्र ने किया रक्तदान, पेश की अनूठी मिसाल

माही की गूंज, थांदला। आज मिशन हॉस्पिटल में एक रक्तदान का ऐसा मामला सामने आया जिसको देखने के बाद सभी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेघनगर निवासी दिनेश वसुनिया की पत्नी श्रीमति रेशमा वसुनिया को बी प्लस ब्लड दो यूनिट की आवश्यकता थी। ऐसे में ये बात झाबुआ जयस के संरक्षक वीरसिंह भाबर को पता चली तो अपने पुत्र चिराग भाबर को लेकर मिशन हॉस्पिटल थांदला पहुंचे। जहां दोनों पिता-पुत्र ने एक-एक यूनिट ब्लड डोनेट कर एक अनूठी मिसाल पेश की। थांदला ही नहीं वरन जिले में शायद पहला मौका होगा किसी मरीज की जान बचाने के लिए पिता-पुत्र एक साथ आगे आए। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के कम ही लोग रक्तदान को समझते है, ऐसे में इन पिता-पुत्र के एक सफल प्रयास से अवश्य ही जागरूकता आएगी।

झाबुआ एसपी का हुआ तबादला आशुतोष होंगे नए एसपी

माही की गूंज, झाबुआ। एमपी पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। यहां 39 पुलिस कप्तानों के तबादले किए गए है। पुलिस कप्तानों के तबादले की लिस्ट जारी की गई है। जिसमें झाबुआ के पुलिस कप्तान विनित जैन का तबादला कर उनकी जगह पर नए पुलिस कप्तान के रूप मे आशुतोष को झाबुआ पुलिस विभाग की कमान सौंपी गई है।

अरोड़ा आइसना के मध्यप्रदेश व गुजरात राज्य के संगठन प्रभारी नियुक्त

माही की गूंज, झाबुआ। आल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन (आइसना) के प्रदेश उपाध्यक्ष कुन्दन अरोड़ा को संगठन के प्रति सक्रियता को देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। आइसना के प्रदेश अध्यक्ष विनय डेविड की अनुशंसा व राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवशंकर त्रिपाठी की सहमति पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व संगठन प्रभारी ग्यारसीलाल शर्मा द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संगठन प्रभारी मनोनीत करते हुए मध्यप्रदेश व गुजरात राज्य का प्रभार सौंपकर दोनों राज्यों में संगठन पदाधिकारियों का मनोनयन करने व संगठन को सक्रिय बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

जिला महामंत्री और मंडल अध्यक्ष पद के बीच उलझा रायपुरिया मंडल अध्यक्ष का पद

रायपुरिया -झकनावदा क्षेत्र से सामने आ रहे है अलग-अलग दावेदार

माही की गूंज, पेटलावद।

दूसरे मंडलों की तरह रायपुरिया के लिए भी जोड़-तोड़ का दौर चल रहा है। यहां भाजपा के सामने डबल चुनौती की स्थिति है। यहां भाजपा को फिर से अपनी जमीन तैयार करनी है तो निर्मला और गुमान को भी साधना हैं। ऐसे में यहां से मंडल अध्यक्ष जिसको भी बनाया जाना है वो स्वयं के प्रभाव वाला हो सकता है। रायपुरिया मंडल से निर्मला भूरिया की दूरी और गुमान की केवल निजी समर्थकों से निकटता के चलते दोनों अपना प्रभाव नहीं बना पा रहे हैं। पेटलावद से राजनीतिक करियर के सपने देखने के बाद से लेकर सांसद बनने तक गुमानसिंह भाजपा में यहां अपने पैर नहीं जमा पाए। जिसका मुख्य कारण अपने गिने-चुने निजी समर्थकों को ही समय देकर, भाजपा नेता और संगठन को दरकिनार करना। रायपुरिया मंडल के पचासों दौरों के दौरान मंडल अध्यक्ष के साथ- साथ अधिकांश पदाधिकारी साथ नहीं दिखे। न ही उनको सांसद के आने की कोई सूचना दी गई। भीड़ बढ़ाने के लिए पेटलावद और ग्रामीण मंडल के निजी समर्थकों को बुलाया जाता रहा और रायपुरिया मंडल के पुराने भाजपा नेताओं से किसी प्रकार की कोई मुलाकात नहीं की गई। यहां सांसद की कांग्रेसी नेताओं से निकटता भी जग जाहिर है। जिससे भाजपाई नेता खफा हैं। पूरे मंडल में वर्चस्व की लड़ाई जारी रही,भले ही गुमानसिंह यहां अपनी ताकत दिखाने में कामयाब रहे, लेकिन भाजपा में अपनी साख बनाने में पूरी तरह असफल रहे हैं। अब मंडल में अपनी टीम बैठाकर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है।

वर्तमान अध्यक्ष अजमेरसिंह भूरिया की वापसी के कयास

रायपुरिया मंडल को लेकर पार्टी के पास गिने-चुने ही नाम है। वतर्मान में रायपुरिया मंडल से अजमेरसिंह भूरिया जो कि अभी जिला महामंत्री पद के बड़े दावेदार हैं, मंडल अध्यक्ष के रूप में दोबारा वापसी कर सकते हैं। मंडल में जितने भी नाम अब तक सामने आ रहे हैं, उनमें से अधिकांश अजमेर की वापसी होने पर अपनी दावेदारी सिलेंडर करने को भी तैयार हैं। जिला कार्यकारिणी की पहले घोषणा होगी। ऐसे में अगर अजमेर का नाम जिला महामंत्री पद के लिए नहीं दिखा तो मंडल अध्यक्ष पद पर इनकी दोबारा वापसी हो सकती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में यह गुमानसिंह गुट की बड़ी हार से कम नहीं होगा। क्योंकि रायपुरिया मंडल अध्यक्ष होने के बाद भी अजमेरसिंह को सांसद की ओर से मान सम्मान नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के बाद गुमान द्वारा मंडल अध्यक्ष पर लगाए गए आरोप के बाद से अब तक ठनी हुई है। अनुभव और पूरे मंडल में बूथ स्तर पर पहुंच के चलते अजमेरसिंह भूरिया के वापसी के प्रयास किए जाने तय है। क्योंकि स्थानीय चुनावों में कांग्रेस से मिलने वाली चुनौती से पार पाने के लिए किसी भी नए व्यक्ति पर भरोसा करना भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता हैं। रायपुरिया मंडल में पार्टी हर बार अलग-अलग झोन से नेतृत्व देती आई है। ऐसे में किसी नए नाम पर झकनावदा क्षेत्र से विचार होता हैं तो संघ की पृष्ठ भूमि से आने वाले अभय वोहरा के नाम पर मंथन हो सकता है। भाजपा में लगातार सक्रिय अभय युवा मोर्चा के महामंत्री और जिला मंत्री के पद पर रहते हुए काम कर चुके है और झकनावदा क्षेत्र में सक्रिय है। गुमानसिंह लगातार झकनावदा क्षेत्र में दौरे पर रहे, लेकिन अभय वोहरा उनके आसपास नहीं देखे गए। न ही गुमान समर्थकों ने इनको सांसद के आसपास आने दिया। निर्मला भूरिया के समर्थक माने जाते हैं और संघ में भी इनकी अपनी लाइन जमी हुई है। जिसके चलते रायपुरिया मंडल की दौड़ में इनका नाम शामिल है। यदि की ट्राइबल चेहरे पर ही पार्टी में मंथन हुआ तो अभय इस रेस में पीछे जरूर रह जाएंगे, लेकिन मंडल के दूसरे महत्वपूर्ण पद पर इनकी नियुक्ति होना तय है।

गुमान समर्थक भी रायपुरिया मंडल की रेस में, जिलाध्यक्ष पर बनाया जा रहा दबाव

रायपुरिया मंडल का रिकॉर्ड देखा जाए तो ज्यादातर मौके रायपुरिया क्षेत्र को ही नेतृत्व करने के लिए मिलते आ रहे हैं। इसलिए इस बार झकनावदा क्षेत्र से मंडल अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठ रही है। गुमानसिंह डामोर खेमे के सांसद प्रतिनिधि राजेश कासवा का नाम भी पद की दौड़ में शामिल है। हालांकि कासवा की राजनीतिक जमीन काफी कमजोर है। इनके पक्ष में गुमनसिंह के अलावा क्षेत्र का कोई भी वरिष्ठ नेता पक्ष में नहीं है। सांसद के लगातार संगठन ने बढ़ते प्रभाव के कारण रायपुरिया मंडल में नाम चर्चा में है, व्यवहार कुशल होने के बाद भी आयातित कांग्रेसी की छाप और केवल गुमान समर्थक के टेग के कारण इस रेस में पीछे रहेंगे ये भी तय है। लेकिन यह गुमानसिंह के संगठन में अपने प्यादे फिट करने का प्लान बी कहा जा सकता हैं। जहां एक नाम को आगे कर किसी दूसरे के नाम पर दबाव डाल कर सहमति बनाई जा सके। पूर्व जिला जनपद सदस्य और पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रह चुके रायपुरिया क्षेत्र के युवा नेता नीलेश मीणा का नाम इस पद के दावेदारों में प्रमुखता से लिया जा रहा है। पेटलावद विकास खण्ड से कोई बड़ा आदिवासी चेहरा अब तक सामने नहीं आया है। नीलेश मीणा को भविष्य की राजनीति का चेहरा बनाकर सामने किया जा सकता है। लम्बा राजनीतिक अनुभव और सांसद की गुड लिस्ट में शामिल नीलेश मीणा का नाम राजेश कासवा के नाम की जगह गुमान गुट द्वारा आगे किया जा सकता है। लेकिन निर्मला भूरिया के विधानसभा क्षेत्र होने के चलते इनकी भूमिका संगठन में रहेगी ये भी तय है। ऐसे में गुमान की निकटता के कारण नीलेश मीना के नाम पर एक तरफा सहमति नहीं बन सकती। कहीं न कहीं निर्मला या फिर उनके करीबी नेताओं को साधना होगा। रायपुरिया-रामनगर के युवा नेता लक्ष्मीनारायण पाटीदार का नाम भी इस रेस का बड़ा हिस्सा बन कर उभरा है। ये बिना टेग वाले नेताओं की श्रेणी में सुमार हैं। जहां बात भाजपा की आती हैं लक्ष्मीनारायण पाटीदार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते है। निर्मला भूरिया से लेकर गुमानसिंह की राजनीति तक सब में तालमेल बनाए हुए हैं। आखरी में अलग-अलग नाम पर गुटबाजी होती हैं तो लक्ष्मीनारायण पाटीदार बीच का रास्ता हो सकते है। और भी कई नाम रायपुरिया मंडल में चर्चा में है जो अपनी-अपनी ओर से लॉबिंग कर रहे हैं। वर्तमान में मंडल के महामंत्री कुलदीप लववंशी का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि की पूरे झकनावदा क्षेत्र में सांसद गुमानसिंह के खिलाफ एक मात्र संगठन के पदाधिकारी हैं जिन्होंने झंडा बुलंद कर रखा हैं। निर्मला भूरिया के कट्टर समर्थक माने जाते है। वर्तमान अध्यक्ष अजमेरसिंह भूरिया को यदि जिला कार्यकारिणी में जगह मिलती है तो इनका भी नाम आगे आ सकता हैं।

खबर का असर... रेत से भरे ट्रेक्टर पकड़े, वाहन चालकों को न्यायालय ने भेजा जेल

माही की गूंज, पेटलावद। माही की गूंज द्वारा रेत के अवैध उत्खनन की खबर प्रमुखता से छपने के बाद सुर्खियों में आई रेत के अवैध उत्खनन के लिए खनिज विभाग तो हरकत में नही आया लेकिन उच्चधिकारियों के निर्देशों के बाद पेटलावद पुलिस ने रेत से भरे तीन ट्रेक्टर जप्त किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेक्टर मालिकों पर कार्यवाही की जा रही हैं। पुलिस के पास भा.द.वि. की धारा 379 ,411 तथा नियम 18 एम पी मिलरन्स प्रोविन्सन ऑफ इनलीगल माईनिंग के तहत कार्यवाही की जाना है। अब तक अवैध रेत का उत्खनन करने वाले और परिवहन करने वाले खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस से लेन-देन कर छूट जाते थे, लेकिन इस बार पुलिस कार्यवाही में पकड़े गए तीनों ट्रेक्टरों के चालको नंदराम खड़िया, कालू निनामा, मुकेश गामड़ को न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से उनको जेल भेज दिया गया। पेटलावद विकास खण्ड का सम्भवतः पहला मामला होगा जहां अवैध रेत परिवहन मामले में किसी को जेल जाना पड़ा। वहीं अवैध तरीके से रेत ढुलाई कर रहे ट्रेक्टरों की अब तक जमानत नहीं हो सकी हैं। इतने सख्त कानून होने के बाद भी पूरे क्षेत्र में रेत का उत्खनन बेरोकटोक जारी है।

12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ शराबी ने कुकर्म करने का किया कृत्य

माही की गूंज, खवासा।

थांदला थाने के खवासा चौकी के अंतर्गत भामल के जंगल में मवेशी चरा रही नाबालिग लड़की के साथ कुकर्म करने का कृत्य किया। जानकारी अनुसार भामल ग्राम पंचायत की ग्राम रूपारेल की 12 वर्षीय नाबालिग बदला हुआ नाम जानकी भामल-मादलदा मार्ग पर जंगल में मवेशी चरा रही थी। तभी बाइक क्रमांक एमपी 45 बीए 7765 पर सवार होकर शराब के नशे में संगत निवासी धुलिया पिता हुरतान कटारा आ रहा था। नाबालिग लड़की को देख धुलिया के मन का राक्षस जाग गया और जानकी को पकड़ने हेतु पिछा किया। जिस पर जानकी भागते हुए हजा बाबजी के आगे बारीवाली नाकी में मेन मार्ग से करीब 200 फीट अंदर जंगल में भागी। वहीं पिछा करते हुए जानकी को धुलिया ने पकड़ लिया और नाबालिग मासूम के साथ जबरदस्ती कर कुकर्म करने का कृत्य किया। भागते हुए जानकी की ओढ़नी भी निकल गई।

जानकी के साथ जंगल में कुछ दूरी पर दो अन्य छोटे बच्चे मवेशी चरा रहे थे। जानकी के बचाओ-बचाओ चिल्लाने पर दोनों बच्चे भागते हुए घर गए। जहां लड़की के माता-पिता को घटना की जानकारी दी। इसी बीच नाबालिग लड़की के चिल्लाने पर एक वृद्ध भगवान के रूप में आया और उसने धुलिया रुपी राक्षस से नाबालिग को छुड़ाया। वहीं लड़की के परिजन भी मौके पर पहुंचे और शराब के नशे में धुत धुलिया के साथ दो-दो हाथ किए और उसे पुलिस चौकी खवासा लाया गया।

नाबालिग की ओढनी भागते समय निकलकर गिरी पडी।

कलयुगी राक्षस धुलिया ने बारीवाली नाकी के इस स्थान पर जगल में नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने का किया था प्रयास।

नाबालिग ने रिपोर्ट में लिखाया कि धुलिया ने मेरा पिछा किया और जगल में मुझे पकड़कर मेरे साथ जबरदस्ती कर मुझे जमीन पर गिरा दिया। मेरे चिल्लाने पर एक बुर्जुग आया जिसने मुझे धुलिया से छुड़ाया और मैं वहा से भागी। जानकी की रिपोर्ट पर थांदला थाने में धारा 354, 7/8 लेंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, पास्को के अंतर्गत प्रकरण पंजिबद्ध किया है। मामले की विवेचना एसआई रूकमणी अहिरवार कर रही है। खवासा नवनियुक्त चौकी प्रभारी रमेश कोली ने बताया कि शराब के नशे में बाईक से संगत निवासी धुलिया आ रहा था कि उसकी नियत नाबालिग लड़की पर खराब हुई और उसके साथ छेड़खानी की जिसपर अपराध पंजीबद्ध हुआ है।

ग्राम पंचायत से 12 किलोमीटर दूर है फलिया, न रोजगार, न पानी, न मिल रहा योजनाओं का लाभ, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

एक भी किसान को नहीं मिला प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ

माही की गूंज, पेटलावद।

आज़ादी के 70 सालों के बाद भी देश-प्रदेश की आई कितनी ही सरकारें आम जनता की मूल समस्या दूर करने तक नहीं पहुंच सकी है। कागजों पर संचालित सैकड़ों योजनाओं को आंकड़े वार दिखाकर वाहवाही लुटी जाती है, लेकिन धरातल पर लोगों को कितना और कैसा लाभ मिला यह देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही एक मामला पेटलावद विकास की कोदली पंचायत का सामने आया है। जहां के लगभग 100 ग्रामीणों ने पेटलावद पहुंच कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है।

ग्राम पंचायत से 12 किलोमीटर दूर बसे मालपाड़ा फलिये की है समस्या

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन को तहसीलदार जितेंद्र अलावा देते हुए बताया कि ग्राम मालपाड़ा ग्राम पंचायत कोदली का हिस्सा हो कर एक फलिया है और फलिये से ग्राम पंचायत कोदली 12 किलोमीटर दूर है। फलिये की जनसंख्या लगभग 600 है लेकिन फलिये के ग्रामीण आज तक शासन की कई योजनाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने बताया कि मालपाड़ा के किसानों को आज तक प्रधानमंत्री सम्मान निधि नहीं मिली। न ही आज तक एक भी मकान प्रधानमंत्री आवास में स्वीकृत हुआ। वैसे तो मालपाड़ा पेटलावद से मात्र 03 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आवाजाही के लिए बना कच्चा रास्ता जहां आये दिन दुर्घटना का भय बना रहता है। बारिश में पूरी तरह से बन्द हो जाता है। फलिये में आने-जाने के सभी मार्ग जल भराव के कारण बन्द हो जाते है। बीमार लोगों को अस्पताल तक भी नहीं पहुंचाया जा सकता। न ही बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता हैं। फलिये में कोई सीसी रोड तक नहीं है। जिससे फलिये में भी आवाजाही तक मुश्किल हो रही है। छोटे-छोटे काम के लिए ग्रामीणों को 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हैं और बारिश में यही दूरी 17 किलोमीटर हो जाती हैं। वहीं बारिश में कोई भी कर्मचारी सभी रास्तों पर नाले पुर होने से गांव में नहीं आ पाते है।

न सिंचाई के लिए पानी, न पीने के लिए, मतदान के लिए जाना पड़ता हैं 03 किमी

लगभग 600 की जनसंख्या वाले इस फलिये के लोगों के पास सिंचाई के लिए पंचायत के एक मात्र निस्तार तालाब के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जहां से बमुश्किल एक बार पानी मिल पाता है। ग्राम पंचायत द्वारा इस फलिये के एक भी किसान को कपिल धारा कूप का लाभ तक नहीं दिया गया। वहीं यहां के ग्रामीण पीने के पानी तक के लिए जूझते है। 600 लोगों के बीच एक मात्र हैडपम्प हैं, जिससे इनकी पीने के पानी पूर्ति होती हैं। विधानसभा-लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए भी मालपाड़ा के ग्रामीणों को तीन किलोमीटर दूर दुलाखेड़ी पंचायत जाना पड़ता है।

नहीं मिली प्रधानमंत्री सम्मान निधि

केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली 6 हजार रुपए की सम्मान निधि यहां मालपाड़ा के एक भी किसान को आज तक नहीं मिल सकी हैं। यहां के किसानों के नाम कोदली पंचायत में और कृषि भूमि पेटलावद हल्के में आती है। जिससे शासकीय खानापूर्ति में परेशानी आ रही हैं। जिससे यहां अब तक एक भी किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सका है।

ग्रामीणों ये रखी मांग

एक समय पेटलावद नगर परिषद में मालपाड़ा आज से 20 से 25 वर्ष पहले जुड़ा हुआ था। इसे कब अलग कर दिया, पता नहीं चला। अब मालपाड़ा के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पंचायत 12 किलोमीटर दूर होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मालपाड़ा को राजस्व गांव बना कर पेटलावद नगर परिषद या दुलाखेड़ी पंचायत से जोड़ा जाए जो कि मालपाड़ा से मात्र 03 किलोमीटर की दूरी पर है। जिससे गांव के लोग शासन की मुख्य धारा से जुड़ सके और शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके।

तहसीलदार जितेंद्र अलावा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते ग्राम मालपाड़ा के ग्रामीण।

विधायक के वार्डवासियों को परेशान होकर खुद पहुंचना पड़ा नगरपालिका

माही की गूंज, झाबुआ।

अति का अंत होता है, जिसका जिता जागता उदाहरण मंगलवार को नगर के रहवासियों के द्वारा दिखाई दिया। जिसमें रहवासियो के द्वारा अपनी समस्याओं को कई बार नगरपालिका में बताने के बाद भी उसका निराकरण नहीं हो पा रहा था। जिसके कारण रहवासियों के साथ वार्ड पार्षद सहित कांग्रेस तथा भाजपा के लोग भी एक साथ मिलकर समस्या को दूर करने के लिए नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए।

नगर के वार्ड क्रमाक 12 गोपाल कॉलोनी जहां पर जनप्रतिनिधि कांग्रेस विधायक कातिलाल भूरिया का निवास स्थना है। इसके अलावा जहां पर नगरपालिका अध्यक्ष मन्नू बेन डोडियार के रहने के बावजूद नगरपालिका के कार्यों में देरी हो रही हैं। रहवासियों को जनप्रतिनिधियों को छोड़ स्वयं नगर पालिका कार्यालय तक पहुंचकर धरना देने की बात करना पड़ रही है। आखिर रहवासी कितने परेशान हो गए कि उन्हे सीएमओ एलएस डोडिया के पास खुद अपनी शिकायतों को लेकर जाना पड़ा।

वार्ड क्रमाक 12 गोपाल कॉलोनी में सबसे प्राथमिक मांगों में से एक समस्त वार्ड की नाली निर्माण का कार्य विगत वर्षों से कई बार आग्रह करने के बाद भी नहीं हो पाया। ना ही उसकी फाइल तैयार हुई और ना ही कार्यवाही हो पाई। वार्ड क्रमांक 12 में नाली निर्माण की शुरू से मांग की जा रही है, लेकिन नगरपालिका को कई बार मौखित बोलने के बावजूद एक भी नाले की प्रक्रिया में कोई तेजी देखने को नहीं मिली। वार्ड के रहवासी दौलत भावसार के घर के पास नाली पर जाली मरम्मत का भी 1 महीने से सीएमओ को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद कु. आयुषी भाबोर ने अपने लेटर पेड पर ही उक्त समस्याओं से सीएमओ एलएस डोडिया को अवगत कराया। वहीं उसमे यह तक लिखा गया कि उक्त कार्य में अगर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं की जाती है तो मजबूरन मुझे अपनी ही कांग्रेस परिषद् के खिलाफ उग्र आंदोलन व धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। इस पर सीएमओ एलएस डोडिया ने उक्त कार्यो को जल्द से जल्द पुरा करने का आश्वासन भी दिया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422